वर्ष : 17 ❖ अंक : 346 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक

मंगलवार, 25 जुलाई 2023

अमित शाह ने विपक्ष से की मणिपुर पर चर्चा होने देने की अपील 3

सिद्दारमैया समर्थकों ने की हरिप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग 8

प्रत्येक परिवार से सेना में हो एक सदस्य : सीएम

कहा– इस विचार को प्रतिपादित करने के लिए सरकार करेगी हर तरह का समर्थन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 जुलाई । सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने आज राज्य के पूर्व सैनिकों की बेहतरी हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये आर्थिक अनुदान राशि के अलावा पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की।

आज स्थानीय चिंतन भवन में सिक्किम वीर गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण एसोसिएशन द्वारा पूर्व सैनिकों की सेवाओं और योगदान के सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा राई के अलावा सम्मानित अतिथि के रूप में राज्य के श्रम मंत्री एलएन शर्मा, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉ राजन ग्रेवाल, अखिल भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरएस छेत्री, गंगटोक के जीओसी कर्नल विवेक कुलकडिया एवं विभिन्न जिलों से आये गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

यहां अपने संबोधन में मुख्यमंत्री गोले ने इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर आभार जताते हुए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सैन्य बलों के अटूट समर्पण और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान करना है। साथ ही उन्होंने युवाओं को सैन्य बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को सैन्य भर्ती के लिए प्रेरक प्रशिक्षण पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य को सेना में शामिल होने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने इस प्रयास में राज्य सरकार के निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया।

इस अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री गोले ने राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए की वार्षिक अनुदान सहायता राशि की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की रेफरल चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के साथ ही पूर्व सैनिकों द्वारा रखी गई पिछली मांगों की समीक्षा करने का भी आश्वासन दिया। इन मांगों में युद्ध स्मारक की स्थापना, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान, सिंगताम बाजार में एक मेमोरियल पार्क का निर्माण और नामची में एसोसिएशन और सैनिक भवन के स्थायी स्थान का आवंटन शामिल हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा 18 सितंबर को हरितालिका तीज महोत्सव का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने की भी घोषणा की।

वहीं, इस दौरान श्रम मंत्री एलएन शर्मा ने कहा कि राज्य और देश के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान के सम्मान में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उन्होंने आगामी वर्षों में राज्य के युवाओं को सैन्य बल में शामिल होने के लिए प्रेरक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक सैनिक बोर्ड स्थापित के महत्व पर भी जोर दिया।

कार्यक्रम को अखिल भारतीय गोर्खा पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरएस छेत्री ने भी संबोधित किया। उन्होंने संगठन के प्रति अटूट समर्थन हेतु मुख्यमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए संगठन की स्थापना और इतिहास के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेवाओं के संचालन में संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने राज्य के युवाओं से आगे आकर आरक्षित कोटे का लाभ लेते हुए सैन्य बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त, सिक्किम वीर गोर्खा पूर्व सैनिक कल्याण संघ के मुख्य सलाहकार हरि शंकर ने 1 दिसंबर, 2019 को संगठन की स्थापना के बाद से इसके इतिहास के बारे में बताया।

वहीं, संघ की अध्यक्ष श्रीमती पवित्रा दहाल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए देश के लिए सैन्य बलों के उल्लेखनीय योगदान पर जोर दिया और संगठन की स्थापना, लक्ष्य और उद्देश्यों का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बीएसएफ से सेवानिवृत्त एएसआई आरबी सुब्बा ने भी वक्तव्य रखा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिक्किम संस्कृति की पारंपरिक प्रथाओं को प्रदर्शित करते हुए गैरी खेत नामक एक वीडियो एल्बम का अनावरण भी किया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व सैनिक मिलन राज्य में एक अग्रणी कार्यक्रम है, जिसमें सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मी शामिल हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश सेवा में सैन्य बलों द्वारा प्रदर्शित अटूट समर्पण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है।

सीएम ने प्रेस क्लब को सौंपा ट्रैवलर वाहन

सिक्किम सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : गोले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 जुलाई । सिक्किम सरकार की ओर से आज प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम को आधिकारिक रूप से ट्रैवलर वाहन की चाबी सौंप दी गई। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने आज सुबह अपने आधिकारिक आवास मिंटोकगांग में एक कार्यक्रम में प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम अध्यक्ष शेखर खवास को इस 17 सीटर वाहन की चाबी सौंपी। गौरतलब है कि हाल ही में आयोजित प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम के 21वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने क्लब को यह वाहन प्रदान करने की घोषणा की थी।

आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री गोले ने पीसीएस अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों की पेंशन, सरकारी विज्ञापन प्रावधानों और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए नीति निर्धारण जैसे विभिन्न मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और चिकित्सा सहायता के साथ-साथ अन्य सहायताओं की आवश्यकता वाले लोगों की मदद कर रही है। साथ ही उन्होंने पीसीएस को पेंशन, विज्ञापन बिलों के केंद्रीयकृत भुगतान और डिजिटल मीडिया नीति के संबंध में एक प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया। उन्होंने इन मुद्दों पर गौर करने और संबंधित विभागों व अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान कराने का आश्वासन भी दिया।

आज मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम के दौरान पीसीएस प्रतिनिधिमंडल में क्लब के सभी कार्यकारी सदस्य शामिल थे।

वहीं, इस अवसर पर सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड के सीएसआर गतिविधि के तहत प्रदान किए गए एक कचरा वैन को भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष अरुण उप्रेती को सौंपा। इसके अलावा उन्होंने उत्तर सिक्किम के परियोजना प्रभावित गांवों के लिए एक एम्बुलेंस भी सौंपी। इस अवसर पर विधायक पिंछो नामग्याल लेप्चा और भविष्य भारत के सदस्यगण उपस्थित थे।

यूनाइटेड आर्म रेस्लिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडन ने की राज्यपाल से मुलाकात

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 जुलाई । आज राजभवन में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से यूनाइटेड आर्म रेस्लिंग एसोसिएशन, सिक्किम के अध्यक्ष श्री गणेश कुमार सुब्बा एवं कार्यकारी सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की।

इस भेंट वार्ता के दौरान यूनाइटेड आर्म रेस्लिंग एसोसिएशन की आगामी योजनाओं, उद्देश्यों और खिलाड़ियों के प्रगति के बारे में चर्चा की गई जिस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमारे राज्य के खिलाड़ियों में अद्भुत प्रतिभा है, उन्हें राष्ट्रीय एवं विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने के लिए बढ़ावा देना आवश्यक है।

राज्यपाल ने उक्त एसोसिएशन के कार्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि यूनाइटेड आर्म रेस्लिंग एसोसिएशन युवाओं की क्षमता को दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य कर रही है। राज्यपाल महोदय ने इस दिशा में और अधिक जागरुकता फैलाने और टीम स्पिरिट को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।

यूनाइटेड आर्म रेस्लिंग एसोसिएशन 2016 से स्थापित संस्था है और संस्था द्वारा सितंबर 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन करने का निश्चय किया गया है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हो लेप्चा भाषा : अधिकारी

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 जुलाई । हाम्रो सिक्किम पार्टी ने संविधान की आठवीं अनुसूची में लेप्चा भाषा को शामिल किए जाने की मांग उठाई है। पार्टी के अनुसार, वर्तमान में देश की 22 आधिकारिक भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ऐसे में लेप्चा भाषा जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग में एक लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, को भी संरक्षित और प्रचारित किये जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि यूनेस्को ने भी लेप्चा भाषा को लुप्तप्राय भाषा की श्रेणी में रखा है।

हाम्रो सिक्किम पार्टी के महासचिव बिराज अधिकारी ने विज्ञप्ति में कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भाषाई विरासत की भूमि सिक्किम को अपनी असंख्य भाषाओं पर गर्व है, जिनमें से प्रत्येक भाषा अपने समुदायों की विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में हाम्रो सिक्किम पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि राज्य के विभिन्न समुदायों द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा, अत्यंत सम्मान और मान्यता की पात्र है।

अधिकारी के अनुसार, संसद के चालू मानसून सत्र में चर्चा के लिए निर्धारित यह विधेयक प्रत्येक सिक्किमवासी के लिए गौरव का क्षण पेश करता है। ऐसे में हमारी पार्टी राज्य में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए बोली जाने वाली सभी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबंधी दृढ़ सिद्धांत पर कायम है। यह न केवल गर्व की बात है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ऐसे में, हम सिक्किम के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से लेप्चा भाषा को यह सम्मान प्रदान करवाने वाले विधेयक को अपना समर्थन देने का आग्रह करते हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, हम सिक्किम सरकार से इसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को समर्थन देने का भी आह्वान करते हैं। एचएसपी नेता के अनुसार, इस तरह का एकीकृत प्रयास सिक्किम की विभिन्न भाषाई विरासत को संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी भाषाओं को वह सम्मान दिया जाए जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने कहा, इस दिशा में हमारा समर्थन हमेशा जारी रहेगा।

अच्छी सरकार का मानक लोगों के जीवन स्तर के आधार पर तय होता है : केएन राई

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 जुलाई । आज पश्चिम सिक्किम के सोरेंग जिला अंतर्गत दरामदिन बाजार के हाटघर में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) की दरमदिन समिति की आम बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केएन राई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री सोमनाथ पौडयाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। यह जानकारी पार्टी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सोमनाथ पौड्याल ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी दल सरकार का दर्पण होता है, इसकी रक्षा करना सत्ता पक्ष का दायित्व है। श्री पौडयाल ने कहा कि राजनीति करते समय अपनी गरिमा नहीं भूलनी चाहिए और आम लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री पौडयाल ने कहा, सिक्किम के लोगों ने 2019 के चुनावों में सत्ता परिवर्तन देखा है और आज लोग समझ गए हैं कि पुरानी सरकार अच्छी थी, इसलिए लोग 2024 में एसडीएफ को सरकार में वापस करने के लिए तैयार हैं। श्री पौडयाल ने कहा, लोग इसे तुलनात्मक दृष्टि से भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा, एसडीएफ पार्टी लोगों के कल्याण के लिए बनी पार्टी है और यह एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहेगी।

अध्यक्ष केएन राई ने कहा कि एसडीएफ पार्टी 1993 से ही सिक्किम और सिक्किम के लोगों के कल्याण के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल सत्ता और चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति करते हैं लेकिन एसडीएफ पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिक्किम और सिक्किम के

■ शेष पृष्ठ ०३ पर

छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करें शिक्षक : विधायक आदित्य गोले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 जुलाई । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छात्र परिषद ने आज बुर्तुक में पहले एडू फेस्ट इंटर स्कूल साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें च्याखुंग विधायक आदित्य गोले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा, कार्यक्रम में शिक्षा सलाहकार एमपी सुब्बा, डीआईईटी के निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक के साथ आमंत्रित सदस्य, प्रिंसिपल, शिक्षक एवं छात्र भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता में गंगटोक, पाकिम और मंगन जिलों के 18 स्कूलों से कुल 170 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर विधायक आदित्य गोले ने कहा कि शिक्षा साहित्यिक उत्सव एक अद्भुत कार्यक्रम है जो साहित्य, पढ़ने और सीखने का जश्न मनाता है। उन्होंने यहां विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए उनमें प्रयास करने हेतु एक ठोस लक्ष्य प्रदान करती है। साथ ही उन्होंने अंतर स्कूल प्रतियोगिताओं को छात्रों के समग्र विकास में रचनात्मकता और सीखने के जुनून जैसे गुणों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया। उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी।

इस दौरान, विधायक ने लैब स्कूल के लिए खिलौनों और शिक्षा किटों के प्रथम दान को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने डीआईईटी भवन में बिब्लियोथेका रीडिंग रूम का भी उद्घाटन किया।

वहीं, शिक्षा सलाहकार एमपी

■ शेष पृष्ठ ०३ पर

एक्सपोर्टर्स मीट का हुआ आयोजन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 जुलाई । गंगटोक स्थित प्रधान डाकघर में स्थापित डाकघर निर्यात केंद्र और पार्सल पैकेजिंग यूनिट सुविधाओं के बारे में निर्यातकों को अवगत कराने के लिए सिक्किम के पोस्टमास्टर जनरल कर्नल अखिलेश कुमार पांडे ने रविवार को स्थानीय एक होटल में एक्सपोर्टर्स मीट आयोजित की। इसमें कई निर्यातकों एवं उद्यमियों ने भाग लिया। इसमें सिक्किम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राज्य के वाणिज्य व उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा एमजी मार्ग मार्केट एसोसिएशन और यांगयांग क उद्यमी मौजूद थे।

गौरतलब है कि डाक विभाग द्वारा इसी वर्ष जनवरी में गंगटोक प्रधान डाकघर में डाक घर निर्यात केंद्र और मई में पार्सल पैकेजिंग यूनिट सुविधा की शुरुआत की गई है। आज उक्त बैठक में शामिल लोगों को इनके बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई और निर्यातकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों को कोलकाता के

■ शेष पृष्ठ ०३ पर

डियर साप्ताहिक लॉटरी मुर्शिदाबाद निवासी ने ₹ 1 करोड़ जीते

मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के श्री अमित हसन ने 29.05.2023 को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नम्बर 96G 65030 है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज़ क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। "मैंने इस युवावस्था में ही एक करोड़पति बनने की कभी अपेक्षा नहीं की थी। डियर लॉटरी के माध्यम से ईश्वर ने मुझे यह विशाल पुरस्कार राशि उपहार दी है। इस आश्चर्यजनक अवसर के लिए मैं डियर लॉटरी तथा नागालैंड स्टेट लॉटरीज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह हमें भविष्य में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।" विजेता ने कहा।

पीके मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन को लेकर किया सचेत, कहा- इसका असर भविष्य में नहीं बल्कि पहले से ही मौजूद

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सोमवार को जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (डीआरआरडब्ल्यूजी) की बैठक में सावधानी बरतने की ओर इशारा करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं का प्रभाव अब दूर के भविष्य में नहीं है, बल्कि पहले से ही यहां मौजूद है और बहुत बड़ा है।

मिश्रा ने चेन्नई में आयोजित जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (डीआरआरडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रगतिशील परिवर्तन का समय बीत चुका है। हमें नए आपदा जोखिमों के निर्माण को रोकने और मौजूदा आपदा जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारत ने जी-20 की अध्यक्षता के पिछले आठ महीनों के दौरान उत्साहपूर्वक भाग लिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 56 स्थानों पर अब तक 177 बैठकें हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता के भी दर्शन हुए। जी-20 एजेंडा के ठोस पहलुओं में काफी प्रगति हुई और मुझे यकीन है कि डेढ़ महीने बाद होने वाला शिखर बैठक एक ऐतिहासिक आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य समूह की पहली बैठक मार्च में गांधीनगर में हुई थी। तब से दुनिया ने कुछ अभूतपूर्व आपदाएं देखी हैं।

मिश्रा ने चुनौतियों के पैमाने को रेखांकित करने के लिए मुश्किल मौसम की घटनाओं का हवाला दिया, जिनमें लगभग पूरे उत्तरी गोलार्ध के शहरों में गर्मी की भारी लहरें, कनाडा में जंगल की आग और धुंध के कारण उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में शहर प्रभावित हुए और 45 वर्षों में दिल्ली में सबसे खराब बाढ़ की स्थिति शामिल है, जबकि भारत में मानसून का मौसम आधा भी नहीं गुजरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने भी अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों पर प्रमुख चक्रवाती गतिविधि देखी है।

उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं का प्रभाव अब दूर के भविष्य में नहीं है। वे पहले से ही यहां मौजूद हैं और बहुत बड़े हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं और वे पूरे पृथ्वी पर सभी को प्रभावित करते हैं। आज दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है वे इस कार्य समूह के महत्व को रेखांकित करती हैं। मिश्रा ने कहा, हालांकि समूह ने चार महीने की छोटी सी अवधि में काफी प्रगति की है और अच्छी गति पैदा की है, लेकिन इसे और अधिक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस कार्य समूह की महत्वाकांक्षा हमारे सामने आने वाली समस्याओं के पैमाने से मेल खाना चाहिए।

उन्होंने कहा, यह एक तथ्य है कि अलग-अलग देश और वैश्विक प्रयास सक्रिय रूप से इसमे प्रगति चाहते हैं ताकि उनके सामूहिक प्रभाव को अधिकतम किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि संकीर्ण संस्थागत दृष्टिकोण से प्रेरित खंडित प्रयासों को यह समूह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिश्रा ने कहा, हमें समस्या-समाधान दृष्टिकोण से प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि जी-20 ने प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई को पांच प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना है और इसके पीछे अपना पूरा जोर लगा रहा है।

मिश्रा ने कहा कि समूह को आपदा जोखिम में कमी के लिए उपलब्ध वित्तपोषण की विभिन्न धाराओं के बीच अधिक तालमेल करने की आवश्यकता है और जलवायु वित्त को आपदा जोखिम में कमी के लिए वित्तपोषण का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

उन्होंने कई सुझाव देते हुए कहा कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के लाभ जिसे सबसे पहले पीएम मोदी ने प्रस्तावित किया था और कई जी-20 देशों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य लोगों के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया था। इसका प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। मिश्रा ने कहा कि कार्य समूह द्वारा अपनाई गई सभी पांच प्राथमिकताओं में जलवायु परिवर्तन से उबरने के उपायों पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

राज्यसभा को जानकारी दें पीएम मोदी, सदन में चर्चा और वोटिंग हो : खड़गे

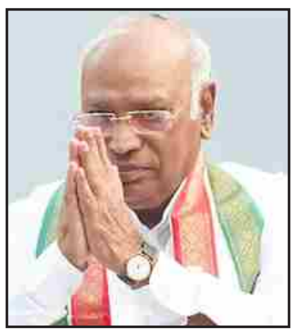

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में अपना बयान रखें, उस बयान पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद इस मुद्दे पर वोटिंग भी कराई जाए।सोमवार को यह बात कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कही।

मणिपुर मामले को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते मानसून सत्र में अभी तक संसद की कार्रवाई एक भी दिन सुचारू रूप से नहीं चल सकी है।

संसद में गांधी प्रतिमा के समीप अन्य विपक्षी सांसदों के साथ धरना दे रहे खड़गे ने कहा कि जब संसद या विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सदन के बाहर बयान नहीं देते।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बयान संसद के बाहर दिया गया। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री संसद के भीतर मणिपुर हिंसा की पूरी जानकारी व बयान दें।

दरअसल, सरकार व राज्यसभा के सभापति शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए राजी हैं। खड़गे ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह कभी आधा घंटा कभी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात कहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नियम संख्या 267 के अंतर्गत सदन में चर्चा कराई जाए। इसके अंतर्गत चर्चा 4 घंटे की भी हो सकती है, उससे अधिक समय भी लिया जा सकता है या पूरा एक दिन भी इस चर्चा को दिया जा सकता है।

कांग्रेस का कहना है कि मणिपुर में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए विपक्ष की यह मांग स्वीकार की जानी चाहिए। इसी टकराव के कारण राज्यसभा में सोमवार को भी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शेष बचे पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है।

विपक्ष का कहना है कि प्रश्नकाल समेत राज्यसभा की सारी कार्रवाई को रद्द करते हुए सर्वप्रथम मणिपुर हिंसा पर विस्तार से चर्चा की जाए। संजय सिंह नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के पास जा पहुंचे। सभापति द्वारा चेतावनी देने के बावजूद संजय सिंह अपने स्थान पर नहीं गए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग और नारेबाजी करते रहे। इस बीच नेता सदन पीयूष गोयल ने सभापति से निवेदन किया कि संजय सिंह को उनके इस व्यवहार के लिए सदन से निलंबित कर दिया जाए। गोयल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी सभापति के सम्मुख दिया। राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों की राय लेने के उपरांत संजय सिंह को शेष बचे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया।

आतंकी चेतावनी पर असम के डीजीपी की दो-टूक, बोले- धमकियों से डरने वाला नहीं, कठोर कार्रवाई करेंगे

गुवाहाटी, 24 जुलाई (एजेन्सी)। असम के डीजीपी जीपी सिंह ने कहा है कि जो भी गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। असम की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। यहां का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अमर उजाला के साथ खास बातचीत में सिंह ने कहा, धमकियां मिलती रहती हैं। धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वाह करना मेरा फर्ज है। उल्लेखनीय है कि रविवार को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (स्व.) की ओर से मीडिया को जारी मेल में डीजीपी जीपी सिंह को असम छोड़ने की धमकी दी गई थी।

जीपी सिंह ने कहा, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (स्व.) असली या नकली के नाम पर जो भी व्यापारियों से जबरन धन वसूली करता पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा। असम के अंदर किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जबरन वसूली के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। इसी तरह से लोगों को खास तौर पर ऊपरी अमस डिब्रूगड़, तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर में जो फोन आ रहे हैं वे अरुणचाल प्रदेश से, या नगालैंड से या फिर म्यांमार से आ रहे हैं। हम इन सबकी जांच भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई असम के किसी भी हिस्से से चिट्ठी देता या फोन करता या मोबाइल पर पैसों की मांग करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।

एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा, हमको प्रदेश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हम तो असम के हित में काम कर रहे हैं। असम की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। सरकार और जनता का प्यार मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग भी जंगल से बाहर आइए, असम की उन्नति के लिए काम कीजिए।

जीपी सिंह ने कहा, मेरे मन में कोई शंका, आशंका या संशय नहीं है। किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। पुलिस आम आदमी को किसी तरह से परेशान नहीं कर रही है। कोई अवैध वसूली करने के बाद अगर भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी। पिछले दिनों जो लोग जबरन वसूली करते हुए पकड़े गए हैं, उनकी जांच चल रही है। राज्य के लोगों को, व्यापारियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

पिछले कुछ दिनों में ऊपरी असम में व्यापारियों और लोगों को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (स्व.) असली या नकली के नाम पर जबरन वसूली के पत्र मिल चुके हैं। इस संबंध में पुलिस ने दो लोगों को पैसों के साथ गिरफ्तार भी किया है। इस पर रविवार को असम के डीजीपी ने ट्विट किया था कि जो जबरन वसूली के मामले में पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (स्व.) की ओर से मीडिया को मेल भेजकर डीजीपी को धमकी दी गई।

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सच को सामने आने से रोक रहा मुस्लिम पक्ष : विहिप

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में हो रहे एएसआई सर्वे पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया गया है। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर सच को सामने आने से रोकता रहा है और इस बार भी वह यही काम कर रहा है। संगठन ने मांग की है कि अब इस मामले में कोई दांवपेंच स्वीकार न कर ज्ञानवापी का सर्वे कराकर सच को सामने लाना चाहिए।

विश्व हिन्दू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने अमर उजाला से कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर 393 सालों से ज्ञानवापी मामले का सच लोगों के सामने नहीं आने दिया जा रहा है। अब जबकि अदालत के आदेश के बाद वहां पर सर्वे का काम किया जा रहा है, उसे हर हाल में बाधित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष को भी यह पता था कि निचली अदालत के आदेश को सबसे पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, लेकिन सीधे सर्वोच्च न्यायालय आकर समय बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। विहिप ने आरोप लगाया है कि यह सब केवल सर्वे को रोकने की कोशिश है।

विहिप ने कहा है कि बार-बार के हस्तक्षेप से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुस्लिम पक्ष किसी भी कीमत पर सच को सामने आने से रोकना चाहता है। ऐसे में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसी भी आपत्ति के कारण ज्ञानवापी का सर्वे और इस पर आने वाले निर्णय की प्रक्रिया प्रभावित न की जा सके।

मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि सर्वे के बहाने वहां पर खुदाई कर ज्ञानवापी को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन अदालत और एएसआई ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञानवापी में कोई खुदाई नहीं की जा रही है। वहां केवल फोटोग्राफ लेकर भवनों की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। प्राचीनता और निर्माण सामग्री के आकलन के लिए अधिकतम 10 ग्राम मिट्टी लेकर उसकी प्राचीनता का आकलन किया जाएगा।

भारतीय रॉकेट पीएसएलवी 30 को सिंगापुर के सात उपग्रहों के साथ भरेगा उड़ान

चेन्नई, 24 जुलाई (एजेन्सी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 30 जुलाई को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) का उपयोग करके सिंगापुर के सात उपग्रहों को लॉन्च करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सोमवार शाम से प्रक्षेपण देखने के इच्छुक लोगों का पंजीकरण शुरू करेगा।

अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, पीएएसएलवी-सी56 कोड वाला पीएसएलवी रॉकेट मुख्य रूप से लगभग 360 किलोग्राम वजनी सिंगापुर के डीएस-एसएआर उपग्रह को ले जाएगा।

अन्य छह छोटे उपग्रह वीईएलओएक्स-एएम, एआरसीएडीई, एससीओओबी-दो, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर से हैं; एनयूएलआईओएन, एनयू स्पेश पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर से संबंधित है, गैलासिया-2, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर से और ओरआरबी-12 एसटीआरआईडीईआर एलिना पीटीई, लिमिटेड, सिंगापुर है।

इसरो ने कहा कि पीएसएलवी-सी56 रॉकेट को प्रारंभिक उड़ान चरण के दौरान अतिरिक्त जोर देने के लिए अतिरिक्त स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के बिना इसके कोर-अलोन मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है।

यह डीएस-एसएआर उपग्रह को 5 डिग्री झुकाव और 535 किमी की ऊंचाई पर निकट-भूमध्यरेखीय कक्षा (एनईओ) में लॉन्च करेगा।

डीएस-एसएआर उपग्रह डीएसटीए (सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व) और एसटी इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है।

एक बार तैनात और चालू होने के बाद, इसका उपयोग सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं का सहयोग करने के लिए किया जाएगा।

एसटी इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए मल्टी-मॉडल और उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी और भू-स्थानिक सेवाओं के लिए इसका उपयोग करेगी।

डीएस-एसएआर इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) द्वारा विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) पेलोड रखता है। यह डीएस-एसएआर को हर मौसम में दिन और रात की कवरेज प्रदान करने की अनुमति देता है, और पूर्ण पोलारिमेट्री पर एक मीटर रिज़ॉल्यूशन पर इमेजिंग करने में सक्षम है।

दूसरी ओर, वीईएलओएक्स-एएम, एक 23 किलोग्राम प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माइक्रोसैटेलाइट है; आर्केड एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर (आर्केड) एक प्रायोगिक उपग्रह है; एससीओओबी-दो, एक 3यू नैनो उपग्रह, जो एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक पेलोड उड़ा रहा है। एनयूस्पेश द्वारा एनयूएलआईओएन, एक उन्नत 3यू नैनो उपग्रह, जो शहरी और दूरस्थ दोनों स्थानों में निर्बाध आईओटी कनेक्टिविटी को सक्षम करता है। इसरो ने कहा, गैलासिया-2, एक 3यू नैनो उपग्रह जो पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करेगा और ओआरबी-12 स्ट्राइडर उपग्रह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत विकसित किया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि पीएसएलवी-सी56 रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट में पहले लॉन्च पैड से लॉन्च होगा।

प्रस्तावित रॉकेट मिशन लगभग दो सप्ताह की अवधि में इसरो के लिए दूसरा रॉकेट मिशन है।

14 जुलाई को इसरो रॉकेट एलवीएम ने चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित किया।

अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी-सी 56 रॉकेट को लिया है।

खतरे के निशान से फिर ऊपर यमुना, लोहा पुल पर रेल यातायात बंद

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। यमुना नदी का जलस्तर सोमवार सुबह खतरे से निशान 205.33 मीटर से एक मीटर से अधिक ऊपर रहा, जिसके कारण प्राधिकारियों ने ओल्ड रेलवे ब्रिज (ओआरबी) पर रेलगाड़ियों का आवागमन रोक दिया।

ओआरबी पर नदी का जलस्तर 13 जुलाई को 208.66 मीटर के अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ दिन से खतरे के निशान के आस-पास है।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से नदी में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया था।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ओआरबी पर रेलगाड़ियों का परिचालन यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा, दिल्ली और शाहदरा के बीच मार्ग बंद रहेगा और रेलगाड़ियों को नयी दिल्ली के रास्ते भेजा जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, नदी के जलस्तर में वृद्धि से राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में राहत एवं पुनर्वास के काम पर असर पड़ सकता है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के आंकड़ों के अनुसार, यमुना का जलस्तर शनिवार रात 10 बजे 205.02 मीटर से बढ़कर रविवार देर रात तीन बजे 206.57 मीटर पर पहुंच गया।, जिसके बाद इसमें गिरावट आने लगी।

आंकड़ों के मुताबिक, जलस्तर सोमवार सुबह आठ बजे 206.54 मीटर दर्ज किया गया, जिसके अपराह्न दो बजे तक गिरकर 206.42 मीटर पहुंचने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।

सीडब्ल्यूसी के आंकड़ों के मुताबिक, यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज में जल प्रवाह की दर शनिवार सुबह नौ बजे एक लाख के आंकड़े के पार चली गई और सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच दो लाख से 2.5 लाख क्यूसेक के बीच रही।

दिल्ली सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश से निचले इलाकों में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर असर पड़ेगा और उन्हें लंबे समय तक राहत शिविरों में रहना पड़ सकता है।

इससे शहर में जल आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है, जो वजीराबाद पंप हाउस में बाढ़ के कारण चार-पांच दिन तक प्रभावित रही थी।

पंप हाउस वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला शोधन संयंत्र में अशोधित जल की आपूर्ति करता है। ये संयंत्र शहर को करीब 25 फीसदी जल की आपूर्ति करते हैं।

दिल्ली को इस महीने अप्रत्याशित जलभराव और बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक के संजय चंद्रा की पत्नी को बेल पर बहस स्थगित

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उन्हें जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

चंद्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, 'वह अक्टूबर 2021 से जेल में हैं। आपको (ईडी) उनकी क्या जरूरत है? उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, 'यह एक ऐसा मामला है जहां कोई जमानत नहीं दी जा सकती। यह करोड़ों रुपये, 10 हजार करोड़ रुपये की एक बड़ी धोखाधड़ी है।''

मामले को सबसे आखिर में सूचीबद्ध किया गया था। समयाभाव के कारण अदालत ने सुनवाई बाद के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले 16 जून को सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने प्रीति चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, हाई कोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा था कि आदेश 16 जून तक प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आदेश को चुनौती देने के लिए समय मांगा था।

घर खरीददारों की शिकायतों पर यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

जांच एजेंसी ने 2021 में यूनिटेक ग्रुप के संस्थापक रमेश चंद्रा, प्रीति चंद्रा और कार्नोसाइट ग्रुप के राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था। यह आरोप लगाया गया है कि यूनिटेक लिमिटेड, जहां आरोपी रमेश चंद्रा चेयरमैन हैं, सह-आरोपी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा निदेशक हैं, ने आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से धन एकत्र किया।

हालांकि, ईडी के मुताबिक, फंड का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे इकट्ठा किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने इस राशि को कई अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया, आरोपी व्यक्तियों ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन द्वीप में स्थानांतरित कर दिए।

ईडी के मुताबिक, आरोपी प्रीति चंद्रा को अपनी कंपनी प्रकौस्ली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपराध से 107.40 करोड़ रुपये मिले।

अमित शाह ने विपक्ष से की मणिपुर पर चर्चा होने देने की अपील

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में विपक्षी दलों से मणिपुर पर चर्चा होने देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार मणिपुर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और वे विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होने दें।

सोमवार को दोपहर बाद 2:30 बजे लोक सभा की कार्यवाही चौथी बार शुरू होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा कि वे इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। वह विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दें। शाह ने इसे महत्वपूर्ण मामला बताते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं चाहता है।

शाह ने विपक्षी दलों से मणिपुर पर सदन में चर्चा होने देने का आग्रह करते हुए कहा कि चर्चा होनी चाहिए और देश को इस संवेदनशील मामले की सच्चाई पता चलनी चाहिए। लेकिन, विपक्ष मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा रहा और लगातार हंगामा-नारेबाजी भी करता रहा।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के मामले में नोडल मिनिस्ट्री, जो कि गृह मंत्रालय है, वही जवाब देता है और विपक्ष नई परंपरा (प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर) स्थापित करना चाहता है, जो उचित नहीं है।

लेकिन, अमित शाह के आग्रह और ओम बिरला की अपील के बावजूद सदन में हंगामा और नारेबाजी जारी रही। जिसे देखते हुए बिरला ने सदन की कार्यवाही को मंगलवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

छात्रों को ज्ञान और ......

सुब्बा ने समाज में शिक्षकों की महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि वे शिक्षा और ज्ञान प्रसार के प्राथमिक एजेंट हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से एक मार्गदर्शक के रूप में छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने का आग्रह किया, जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सरकार राज्य में उच्च शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में लोअर बुर्तुक जूनियर हाई स्कूल की पीआरटी श्रीमती रत्ना लक्सोम सुब्बा को छात्रों की पत्रिका प्रकाशित करने में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। वहीं, इस दौरान तीसरे सेमेस्टर के छात्रों द्वारा प्रयास विषय पर नाटक और चौथे सेमेस्टर के छात्रों द्वारा सामूहिक नृत्य भी पेश किया गया। इस दौरान, डीआईईटी के प्रिंसिपल छिरिंग वांग्दी भूटिया ने भी वक्तव्य रखा।

आज उक्त प्रतियोगिता में तीसरी एवं छठी-सातवीं कक्षाओं की दो श्रेणियों में चार गतिविधियाँ शामिल थीं। इनमें स्पेल बी, एलोक्यूशन, एक्सटेम्पोर, कविता पाठ और क्विज प्रतियोगिताएं हुईं। प्रत्येक गतिविधि में शीर्ष तीन छात्रों का चयन कर उन्हें ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इनमें तादोंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने प्रथम, देवराली गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने द्वितीय और मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

अच्छी सरकार का मानक .....

लोगों की सुरक्षा, कल्याण और भविष्य को ध्यान में रखकर राजनीति करती है। श्री राई ने कहा, अच्छी सरकार का मानक लोगों के जीवन स्तर के आधार पर तय होता है। आज सिक्किम में हालात अच्छे नहीं हैं, लोगों का जीवन स्तर गिर गया है। आय का कोई साधन नहीं है, राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। उन्होंने कहा, एसडीएफ पार्टी और इसके नेता श्री चामलिंग का अपने वादों पर अमल कर लोगों के हित में काम करने का इतिहास रहा है। लोग जानते हैं कि एसडीएफ ने पूरे सिक्किम का विकास किया है।

केएन राई ने कहा, मुख्यमंत्री पीएस गोले न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बल्कि गृह मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही फरमान जारी कर दिया कि वे लोगों के घर में घुसेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। आज सिक्किम के लोग सुरक्षित नहीं हैं। श्री राई ने हाल ही में पारित प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताया और सभी से सिक्किम को बचाने के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।

बैठक में एसकेएम समर्थक ज्ञान बहादुर राई एसडीएफ पार्टी में शामिल हुए। आज की बैठक में युवा मोर्चा संयोजक महेंद्र नालबो, संगठन महासचिव पेमनार्बू शेरपा, युवा मोर्चा उपसंयोजक किशोर गुरुंग, चेली मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती सकुन गुरुंग, युवा मोर्चा प्रभारी रॉबिन तमांग ने वर्तमान सरकार की विफलताओं पर चर्चा की। बैठक में दारामदीन समष्टि के सीएलईसी अध्यक्ष श्री रविलाल गुरुंग ने स्वागत भाषण दिया और सोरेंग जिले के अध्यक्ष एमएस लिम्बू ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। बैठक का संचालन सुमन राई एवं अर्पण परियार ने किया।

एक्सपोर्टर्स मीट का ......

फॉरेज पोस्ट ऑफिस की भूमिका, परेशानी मुक्त कस्टम क्लीयरेंस, गंगटोक डाकघर निर्यात केंद्र के लिए मेल, हब और स्पोक मॉडल की निश्चित मात्रा पर छूट के बारे में जानकारी दी गई।

इसके अलावा कार्यक्रम में पोस्टमास्टर जनरल ने राज्य के डाकघरों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। इसमें रेनॉक डाकघर को सबसे स्वच्छ डाकघर और सिंगताम उप-डाकघर को डाकघर बचत बैंक खाते खोलने के मामले में सर्वश्रेष्ठ डाकघर के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं, ई-कॉमर्स कंपनियों के पार्सल वितरण में मल्ली बाजार डाकघर को डी+0 मेल डिलीवरी और गंगटोक प्रधान डाकघर के नोडल डिलीवरी सेंटर को 95 प्रतिशत डी+0 डिलीवरी के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा, डाक कर्मचारियों के लिए भी प्रेरक सत्र आयोजित किया गया।

राजनाथ सिंह ने विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से की फोन पर बात, संसद में गतिरोध खत्म करने की अपील की

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर की स्थिति से संबंधित अपनी मांगों को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के संबंध में विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। भाजपा सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय उन नेताओं में शामिल हैं जिनसे सरकार ने संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए संपर्क किया है।

उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बीच लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, 'हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर मामला है और स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि राज्य में जो हुआ (बुधवार को वायरल वीडियो में कथित तौर पर दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाते हुए दिखाया गया है) ने पूरे देश को शर्मिंदा किया है।'

रक्षा मंत्री ने पिछले सप्ताह भी मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए सरकार की इच्छा के बारे में सदन में बात की थी। विपक्षी दल मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं और इसके बाद अन्य सभी सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित करके विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं। कई विपक्षी सांसदों ने सोमवार को मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया।

मणिपुर में हिंसा मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार तीसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रहने के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदन में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। उन्होंने सुचारू कार्यवाही के लिए उनसे सहयोग की अपील की। इस बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के के. केशव राव, बीजू जनता दल (बीजद) के सस्मित पात्रा, आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा, सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित कई नेता शामिल हुए।

विपक्ष की मांगों को लेकर 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। सोमवार को विपक्षी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर लोकसभा में नारेबाजी की और तख्तियां दिखाईं। उन्होंने राज्यसभा में भी अपनी मांगों को उठाने की मांग की। 11 अगस्त को समाप्त होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार के पास एक भारी विधायी एजेंडा है।

सुप्रीम कोर्ट का रामनवमी झड़पों की एनआईए जांच के निर्देश वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को राज्य में रामनवमी महोत्सव में हुई झड़पों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि एनआईए को हिंसा की जांच करने का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनी स्वत: संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, '... केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती के अभाव में हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं।'

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए धुएं और आंसूगैस ग्रेनेड को विस्फोटक के रूप में पेश किया गया था।

पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश पुलिस अधिकारियों को हतोत्साहित करता है और इसकी विश्वसनीयता को कम करता है।

दूसरी ओर, एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि झड़पों में बमों का इस्तेमाल शामिल था। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी को विस्फोटकों से जुड़े मामलों की जांच करने का निर्देश दे सकती है, क्योंकि यह एनआईए अधिनियम, 2008 में निर्दिष्ट एक अनुसूचित अपराध है।

27 अप्रैल को इस मामले में एनआईए जांच का आदेश देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. की खंडपीठ ने शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा था कि उन लोगों को ढूंढना राज्य पुलिस की क्षमता से परे है जो झड़पों के लिए ज़िम्मेदार थे या जिन्होंने इसे उकसाया था और इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच जरूरी थी।

एनआईए ने खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के बाद मामले की जांच शुरू की, जिसने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का भी निर्देश दिया था।

इससे पहले, इसी खंडपीठ ने छतों पर जमा हुए पत्थरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में राज्य पुलिस की खुफिया शाखा की विफलता पर सवाल उठाया था। पश्चिम बंगाल में हावड़ा और हुगली जिलों के कुछ हिस्सों में रामनवमी उत्सव पर जुलूसों को लेकर हिंसा हो गई, जो कुछ दिनों तक जारी रही।

19 जून को एनआईए ने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ से संपर्क किया था और पश्चिम बंगाल पुलिस पर इस साल राज्य में रामनवमी झड़पों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपने में असहयोग का आरोप लगाया था।

एनआईए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चूंकि राज्य पुलिस सभी संबंधित दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही है और देरी कर रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी अपनी जांच की गति में तेजी लाने में असमर्थ है।

राज्य सरकार ने दलील दी थी कि वह पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे चुकी है और मामले की सुनवाई वहां लंबित है। हालांकि, एनआईए ने जवाब दिया कि चूंकि देश की शीर्ष अदालत ने अब तक कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।

दूसरे राज्यों का हवाला देने पर भड़के शशि थरूर, बोले- महिलाओं के दर्द का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्स)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मणिपुर की भयावह घटना में महिलाओं की तकलीफ का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष शासित राज्यों में महिलाओं पर हमलों का हवाला देकर इसे बढ़ावा दे रही है। दरअसल, भाजपा पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार की घटनाओं का मुद्दा उठा रही है और विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। विपक्ष इसे हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति पर बहस से बचने के लिए ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहा है।

विपक्ष की इस मांग के बारे में पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर बयान देना चाहिए, थरूर ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, 'मुझे लगता है कि यह (विपक्ष के नजरिए से) समझने योग्य विचार है। आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारा एक राज्य जल रहा है, पड़ोसी राज्य मिजोरम के लिए पहले से ही परिणाम हैं। हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि सरकार के मुख्य कार्यकारी से कम कोई भी इस पर नहीं बोल सकता है, जिसके बाद गृह मंत्री और अन्य अपनी भूमिका निभा सकते हैं।'

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर मीडिया से बात करना उचित समझा, जब संसद का सत्र चल रहा हो, यह स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, संसदीय लोकतंत्र का यही पूरा तर्क है।' थरूर ने एक ट्वीट में कहा कि 'मणिपुर की डरावनी कहानी' में महिलाओं की दुखद पीड़ा का सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा विपक्ष शासित राज्यों में महिलाओं पर हमलों का हवाला देकर 'व्हाटओवर' को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

तिरूवनंतपुरम से सांसद थरूर ने आरोप लगाया, 'जब भी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, राज्य सरकारों ने पीड़ितों के साथ तुरंत और सहानुभूति से कार्रवाई की है, जबकि मणिपुर में अधिकारियों की मिलीभगत है और वे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इन अत्याचारों पर हो-हल्ला मणिपुर संघर्ष के जातीय और सांप्रदायिक तत्वों, गिरजाघरों को अपवित्र करने और जलाने, पुनरुत्थानवादी समूहों के अतिवाद और शक्तिशाली लोगों के संरक्षण में फल-फूल रहे मादक पदार्थों की तस्करी के शातिर व्यापार को छिपाने के लिए भी किया जा रहा है।' थरूर ने कहा कि इनमें से कोई भी तत्व विपक्ष शासित किसी भी राज्य में नहीं पाया जा सकता है।

सरकार मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराने पर सहमत हो गई है और गृह मंत्री इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष पहले प्रधानमंत्री के बयान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध के बीच मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो सका।

'लोग अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, सोच-समझकर ही पोस्ट करें', बॉम्बे हाईकोर्ट की हिदायत

मुंबई, 24 जुलाई (एजेन्सी)। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक धार्मिक समूह के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि किसी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से दूसरों को कुछ बताते समय जिम्मेदारी की भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने 12 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि आजकल व्हाट्सएप स्टेटस का उद्देश्य अपने संपर्क में रहने वालों को कुछ बताना है। पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि लोग अक्सर अपने संपर्क में रहने वालों का व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहते हैं।

पीठ ने 27 वर्षीय युवक किशोर लांडकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में जानबूझकर धार्मिक भावना या आस्था को ठेस पहुंचाने या अपमानित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा, व्हाट्सएप स्टेटस आप जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं या जो कुछ आपने देखा है उसकी तस्वीर या वीडियो हो सकता है, जो 24 घंटे के बाद गायब हो जाता है। व्हाट्सएप स्टेटस का उद्देश्य ही किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स तक कुछ बात पहुंचाना है। यह और कुछ नहीं बल्कि परिचित व्यक्तियों के साथ संचार का एक तरीका है। अदालत ने कहा, किसी को भी दूसरों से कोई बात कहते समय जिम्मेदारी की भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए।

शिकायतकर्ता का मामला यह है कि मार्च, 2023 में आरोपी ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड किया जिसमें उसने एक प्रश्न लिखा और दर्शकों से चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए गूगल पर इसे सर्च करने के लिए कहा। जब शिकायतकर्ता ने सवाल को गूगल पर सर्च किया तो उसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक सामग्री नजर आई।

आरोपी ने दावा किया कि उसका किसी भी धार्मिक समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या जानबूझकर स्टेटस प्रदर्शित करने का इरादा नहीं था और चूंकि व्हाट्सएप स्टेटस केवल वे ही देख सकते हैं जिन्होंने स्टेटस डालने वाले व्यक्ति का नंबर सेव किया है, इसलिए यह तय है कि उसका नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा अपलोड किए गए व्हाट्सएप स्टेटस ने अन्य लोगों को गूगल पर खोज करने और यह पढ़ने के लिए उकसाया कि आरोपी व्यक्ति उनसे क्या चाहता है।

अदालत ने कहा कि एफआईआर प्रथम दृष्टया में आरोपी व्यक्ति के एक विशेष समूह की भावना का अपमान करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे का खुलासा करती है और मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, आवेदक यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि व्हाट्सएप स्टेटस सीमित प्रचलन में है। आवेदक के लिए ऐसे स्टेटस प्रदर्शित करने का कोई औचित्य नहीं है।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR DWARKA MONDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:17 DrawDate on:24/07/23 MRP ₹ 6/-
1st Prize ₹1 Crore/- 73C 33926
Cons. Prize ₹1000/- 33926 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
22016 29211 30355 31881 39456 47345 47883 52505 85078 90422
3rd Prize ₹450/-
0748 1500 1673 2829 2889 3561 4892 5283 5319 8503
4th Prize ₹250/-
0003 0242 1073 4200 5033 5353 6207 6323 6842 9718
5th Prize ₹120/-
0033 0042 0079 0287 0296 0327 0330 0348 0371 0482
0508 0595 0596 0636 0755 0937 1028 1137 1175 1334
1689 1853 2086 2291 2449 2564 2609 2635 2691 2712
2721 2771 2880 3051 3155 3286 3429 3483 3820 4001
4021 4138 4287 4325 4346 4644 4692 4831 4919 4943
4958 5177 5224 5540 5595 5711 5804 5902 6146 6148
6263 6274 6335 6508 6583 6602 7135 7202 7247 7393
7404 7468 7521 7583 7711 7949 8046 8158 8227 8234
8436 8462 8537 8608 8627 8660 8689 8773 8907 8952
9022 9056 9084 9154 9248 9509 9687 9892 9952 9989
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR DESERT MONDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:17 DrawDate on:24/07/23 MRP ₹ 6/-
1st Prize ₹1 Crore/- 95J 47998
Cons. Prize ₹1000/- 47998 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
02186 12174 35096 35295 66071 69111 75932 89248 94905 97096
3rd Prize ₹450/-
0123 0554 3829 4520 6484 6750 7944 8176 8187 9296
4th Prize ₹250/-
1315 2007 4740 4812 5736 6029 7170 8429 9637 9853
5th Prize ₹120/-
0042 0335 0627 0661 0724 0877 0955 1050 1173 1216
1247 1454 1556 1609 1636 1650 1783 2142 2271 2311
2391 2495 2504 2523 2836 2978 3041 3044 3054 3080
3183 3490 3652 3685 3720 3872 4200 4307 4401 4433
4569 4664 4724 4882 5088 5183 5287 5432 5443 5570
5612 5675 5753 5759 5786 5895 5972 6013 6031 6101
6109 6114 6248 6327 6348 6371 6388 6456 6657 6678
6800 6854 7151 7348 7578 7757 7764 7873 7892 7963
8073 8197 8329 8526 8611 8647 8679 8680 8748 8757
8852 8958 8974 9182 9234 9612 9778 9855 9916 9927
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR FINCH MONDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:17 DrawDate on:24/07/23 MRP ₹ 6/-
1st Prize ₹1 Crore/- 35K 97895
Cons. Prize ₹1000/- 97895 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
03492 23017 33992 47107 52900 73789 74166 84658 86800 97603
3rd Prize ₹450/-
0726 1623 2403 2975 3024 5289 6067 6862 8798 9636
4th Prize ₹250/-
0097 0125 0596 0630 1378 6494 7436 7657 8701 9269
5th Prize ₹120/-
0011 0100 0148 0189 0257 0389 0435 0610 0638 0651
0666 0715 0762 0939 1011 1027 1140 1222 1303 1529
1636 1842 1907 1927 2197 2279 2297 2420 2463 2502
2627 2654 2817 2880 2921 3045 3161 3288 3383 3525
3528 3661 3777 3909 3943 4015 4057 4145 4151 4200
4363 4548 4626 4668 4731 4762 4843 4856 5225 5327
5347 5430 5930 6052 6142 6193 6477 6526 6725 6798
6961 6991 7229 7242 7964 8022 8076 8347 8397 8600
8614 8631 8670 8830 8872 8963 9014 9131 9237 9440
9456 9504 9512 9551 9576 9587 9756 9909 9931 9956
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

आग फैलने न दें

मणिपुर में पिछले करीब तीन महीने से जारी दंगों पर रोक लगना तो दूर, अब पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी इसका असर दिखने लगा है। मणिपुर में दो महिलाओं को वस्त्रहीन करके उनकी परेड कराए जाने से जुड़ा एक विडियो वायरल होने के बाद मिजोरम में भी तनाव बढ़ने की खबर है। इसी संदर्भ में शनिवार को पूर्व उग्रवादियों के एक ग्रुप पीएएमआरए ने मिजोरम में रह रहे मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोगों से कहा कि वे जल्द से जल्द मिजोरम छोड़ दें। उसके बाद इन लोगों में घबराहट फैल गई और कई लोग विमान से या सड़क मार्ग से वहां से निकलने लगे। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बेहद खतरनाक है। इसमें दो राय नहीं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ और हो रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। वहां हालात काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि उन कोशिशों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और किन उपायों से उन्हें कारगर बनाया जाए इस पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह कि संसद में उस पर कोई चर्चा तक नहीं हो पा रही। केंद्र और विपक्ष को अविलंब पहलकदमी लेकर इस गतिरोध को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है ताकि मणिपुर की घटनाओं पर राजनीतिक आम सहमति बनती दिखे और वहां हालात संभालने के प्रयासों को और तेज किया जा सके। लेकिन इस बीच यह सावधानी भी बरतना जरूरी है कि मणिपुर की आग अन्य क्षेत्रों में न फैल जाए। यह अच्छी बात है कि मिजोरम से अभी तक हिंसा की कोई सूचना नहीं है। पीएएमआरए की कथित धमकी को भी राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने तत्काल संज्ञान में लिया और पीएएमआरए ने भी यह स्पष्ट किया कि उनकी तरफ से दिया गया बयान अडवाइजरी नेचर का था। लेकिन किसी भी जिम्मेदार संगठन से इस तरह की सलाह की भी उम्मीद नहीं की जाती। अगर देश के किसी हिस्से में कुछ अप्रिय घटा है तो उससे दुख या तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति उन अप्रिय घटनाओं के लिए दोषी हों, गुस्सा भी सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए, सजा की मांग भी उन्हीं के लिए की जानी चाहिए। अगर किसी एक पूरे समूह को उसके लिए दोषी माना या बताया जाने लगे तो यह भी सांप्रदायिक, जातिवादी या नस्लवादी सोच का ही नमूना है। अगर मणिपुर की घटनाओं से मिजोरम में तनाव दिख रहा है तो जिम्मेदार संगठनों को माहौल ठीक करने की कोशिश में जुटना चाहिए जिसका उपाय यह है कि मणिपुर के लोगों को आश्वस्त किया जाए कि आप न घबराएं, हम आपके साथ हैं। यह नहीं कि उन्हें इलाका छोड़ देने की सलाह दी जाए। जरूरी है कि राज्य सरकार ऐसे माहौल में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों से विशेष तौर पर सावधान रहे।

अहम है राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की यात्रा

महेंद्र वेद

मौजूदा जटिल समय में बाइबिल की इस उक्ति का पालन करना बहुत मुश्किल है कि 'अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम करें', खासकर जब पड़ोसियों के साथ अन्य पड़ोसी भी उसी प्रेम, अधिक धन, हथियार और तेल के साथ आपसे प्रतिस्पर्धा करते हों। ऐसे में ख्रयार को 'मदद' का मूर्त रूप लेना होगा, जिससे फर्क पड़ता है। भारत छोटे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, जिनमें से कुछ मित्रवत हैं, तो कुछ नहीं और वे सभी अपने-अपने हितों की रक्षा करने को इच्छुक हैं। जबकि चीन उन्हें भारत से दूर करने के लिए गले लगाने को तैयार है। ऐसे में भारत की मदद को सतर्क एवं प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, साथ ही, यह देखभाल एवं सहयोग के रूप में दिखना चाहिए। प्रत्येक पड़ोसी के साथ भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है, जो आंशिक रूप से भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि चीन का उनके साथ वैसा संबंध नहीं है। संक्षेप में यह भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति को निर्धारित करता है।

पिछले हफ्ते श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आपसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किया, जो पिछले साल श्रीलंका को भारी आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए पिछली सभी समस्याओं, चिढ़ और पूर्वाग्रहों से ऊपर दिखा था। तब भारत ने चार अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया था और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा लगभग तीन अरब डॉलर के राहत पैकेज की सुविधा प्रदान की थी। भारतीय जहाजों ने श्रीलंका की मदद के लिए खाद्य, अन्य जरूरी चीजें और तेल पहुंचाया था, जब उसका आर्थिक संकट एक राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया था और उसे सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा था। भले ही भारत भी ऐसा चाहता हो, लेकिन उस संकट का नतीजा यह हुआ कि राजपक्षे बंधुओं को सत्ता से हटना पड़ा, जो चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाते थे। लेकिन कोई भी देश चीन को दूर नहीं जाने देना चाहता। विक्रमसिंघे ने धैर्यपूर्वक भारत यात्रा की योजना बनाई, जब उसके विदेश मंत्री अली साबरी बीजिंग में थे और राष्ट्रपति स्वयं वहां जाने की योजना बना रहे हैं। इस संक्षिप्त यात्रा का समय और मुद्दा, दोनों का महत्व है। यह श्रीलंकाई राष्ट्रपति के रूप में विक्रमसिंघे की पहली भारत यात्रा थी। इससे पहले छह बार वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भारत का दौरा कर चुके हैं।

दोनों देशों ने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में संयुक्त इरादे के घोषणापत्र और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में आर्थिक विकास परियोजना के लिए भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही, श्रीलंका में यूपीआई एप की मंजूरी के लिए एनआईपीएल एवं लंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता और सैमपुर सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ऊर्जा परमिट का फैसला किया गया। दोनों देशों के बीच बैठक में कनेक्टिविटी, ऊर्जा और आसान वित्तीय लेन-देन पर जोर दिया गया। दिल्ली की यात्रा से पहले विक्रमसिंघे ने संकेत दिया था कि वह ऐसे लेन-देन के पक्षधर हैं, जिसमें भारतीय रुपये की अधिकता शामिल हो। दोनों देशों ने शुक्रवार को हस्ताक्षर करने से पहले हरेक बिंदु पर व्यापक विचार-विमर्श किया। जापान और पेरिस क्लब के अन्य सदस्यों के साथ भारत आधिकारिक ऋणदाता समिति का भी हिस्सा है, और अभी श्रीलंका के साथ एक ऋण उपचार योजना पर बातचीत कर रहा है। चीन, जापान और भारत श्रीलंका के शीर्ष तीन द्विपक्षीय ऋणदाता हैं।

दिल्ली और कोलंबो संभावित संयुक्त उद्यमों की खोज कर रहे हैं, जिसमें वर्षों से लंबित एक एकीकृत ऊर्जा ग्रिड भी शामिल है। भारत यह भी चाहता है कि निजी क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा निवेशक कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश करें, क्योंकि चीन ने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में कोलंबो के दक्षिण में जमीन पर कब्जा करके एक बड़ी पोर्ट सिटी का निर्माण किया है। श्रीलंका चाहता है कि वैश्विक निवेश, खासकर पड़ोसी भारत से उस परियोजना में भारी निवेश हो। भारत का अदाणी समूह एक अरब डॉलर के निवेश के साथ कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में लगा हुआ है। इसके अलावा, पिछले साल भुगतान संतुलन की समस्या के मद्देनजर दिवालिया घोषित होने के बाद श्रीलंका अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए भारत से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है, जो वर्तमान में इसके शीर्ष स्रोत है। कोलंबो स्थित भारतीय सीईओ फोरम को हाल ही में संबोधित करते हुए विक्रमसिंघे ने कहा कि भारतीय मुद्रा जल्द ही श्रीलंका में स्वीकार की जाएगी। यह एक ऐसा कदम है, जो व्यापार और पर्यटन, दोनों को प्रोत्साहित करेगा।

श्रीलंका ने भारतीय कंपनियों से व्यापक निजी निवेश की मांग की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मुलाकात में विक्रमसिंघे ने मछुआरों के मुद्दे पर बातचीत की। भारत श्रीलंका के तमिलों के लिए बेहतर और न्यायपूर्ण समझौते का इच्छुक है, जिस पर बातचीत के दौरान चर्चा की गई। भारत इस उम्मीद में रानिल पर निवेश कर रहा है कि वह काम करेंगे, जबकि राजपक्षे ने बाधा उत्पन्न की थी। फिलहाल विक्रमसिंघे की यात्रा इस लिहाज से एक अच्छा संकेत है कि कर्ज में डूबे होने के बावजूद श्रीलंका आर्थिक सुधार के संकेत दे रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हम मानते हैं कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक-दूसरे की सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करें।' उन्होंने आर्थिक साझेदारी के विजन डॉक्यूमेंट की प्रशंसा की।

मोदी ने कहा कि 'दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिडों को जोड़ने का काम तेज किया जाएगा। यह वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष महत्व रखता है। हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही, भारतीय मूल का तमिल समुदाय श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे कर रहा है।'

श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भारत चिंतित है कि हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने की उसकी योजना एक चुनौती बन सकती है। भारत के चारों तरफ यही कहानी है। ऐसे में केवल धैर्य भरी कूटनीति ही उसकी मदद कर सकती है।

बजट गई लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेदी

विनीत नारायण

पक्ष और विपक्ष अपने-अपने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल तैयार करने में जुट गए हैं। दिल्ली और बेंगलुरू में दोनों पक्षों ने अपना-अपना कुनबा जोड़ा है।

जहां नये बने संगठन इंडिया में 25 दल शामिल हुए हैं, वहीं एनडीए 39 दलों के साथ आने का दावा कर रहा है। अगर इन दावों की गहराई में पड़ताल करें तो बड़ी रोचक तस्वीर सामने आती है।

पिछले चुनाव में एनडीए में अब शामिल हुए इन 39 दलों को मिले वोट जोड़ें तो इस गठबंधन को देश भर में 23 से 24 करोड़ के बीच वोट मिले थे जबकि इंडिया के मौजूदा गठबंधन को 26 करोड़ वोट मिले थे। पर ये वोट इतने सारे दलों में आपसी मुकाबले के कारण बंट गए जिससे इनकी हार हुई। अगर यह गठबंधन ईडी, सीबीआई और आईटी की धमकियों के बावजूद एकजुट बना रहता है, और मुकाबला आमने-सामने का होता है, तो जो परिणाम आएंगे वो स्पष्ट हैं। दूसरा पक्ष यह है कि जहां एनडीए आज 60 करोड़ भारतीयों पर राज कर रही है, वहीं इंडिया संगठन 80 करोड़ भारतीयों पर आज राज कर रहा है, और इसके शासित राज्य भी एनडीए से कहीं ज्यादा हैं। जहां तक परिवारवाद का आरोप है तो दोनों संगठनों में परिवारवाद प्रबल और समान है। अंतर यह है कि जहां एनडीए में शामिल 39 दलों में परिवारवादी नेताओं का कोई जनाधार नहीं है, और उनमें से ज्यादातर दल ऐसे भी हैं, जिनमें एक भी विधायक तक नहीं है जबकि इंडिया संगठन में जो परिवारवाद है, उसके सदस्य दशकों तक राज्यों का शासन चलाने के मामले में अनुभवी और बड़े जनाधार वाले नेता हैं। जहां बीजेपी के नेताओं ने शुरू में दावा किया था कि वो कांग्रेसमुक्त भारत बनाएंगे, वहां आज एनडीए स्वयं ही कांग्रेसयुक्त संगठन बन चुका है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री वो हैं, जो कांग्रेस के स्थापित नेता थे पर ईडी, सीबीआई की धमकियों से डरकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आने वाले चुनाव में इंडिया संगठन को टिकट बांटने में कम दिक्कत आएगी क्योंकि उनके सब दावेदार जनाधार वाले हैं, और कई चुनाव जीत चुके हैं। अलबत्ता, उन्हें अपने अहम और महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाना होगा जबकि एनडीए में शामिल ज्यादातर दल ऐसे हैं, जो आज तक विधायक का चुनाव भी नहीं जीते हैं पर अब लोक सभा के लिए ये सभी अपनी हैसियत से ज्यादा टिकट मांगेंगे।

तब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। बीजेपी का इतिहास रहा है कि शिवसेना जैसे जितने भी दलों ने उसका साथ दिया उन सबको बीजेपी ने या तो अपमानित किया या उनको हड़प ही गई। ऐसे में अबकी बार फिर से एनडीए में शामिल हुए दल अपना अस्तित्व खोने के डर से ग्रस्त रहेंगे। उन्हें इस बात का भी सामना करना पड़ेगा कि आरएसएस उन्हें अपने रंग में रंगने का भरपूर प्रयास करेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडिया संगठन बनने से बीजेपी और एनडीए संगठन के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिसको देखते हुए 2024 का चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है।

जिस तरह भाजपा को विपक्ष के इंडिया नाम के संगठन से आपत्ति हो रही है, उसका असल कारण विपक्ष की एकजुटता है। वरना जब दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी ने अपना नाम बदल कर भारत राष्ट्र समिति कर दिया तो भाजपा या एनडीए के किसी भी सहयोगी दल ने आपत्ति नहीं जताई। विपक्ष की इस एकजुटता को भाजपा आगामी लोक सभा चुनावों में गंभीर चुनौती मान रही है। 2014 में जब नरेन्द्र मोदी लोक सभा चुनाव के मैदान में उतरे थे तब ऐसी कोई चुनौती उनके सामने नहीं थी। इंडिया संगठन बनने के बाद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि विपक्षी दल ना सिर्फ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि एनडीए के खिलाफ युद्ध करने को चुनावी बिगुल भी बजा रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता इंडिया संगठन के अंग्रेजी नाम को लेकर भी काफी असहज दिखाई दिए हैं। इतने असहज कि इंडिया नाम को अंग्रेजों की देन बता कर उसका विरोध भी कर रहे हैं।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर से भी इंडिया को हटा कर भारत रख दिया है। विपक्ष ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि यदि इंडिया नाम से इतनी आपत्ति है, तो क्या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली उन सभी योजनाओं के नाम भी बदले जाएंगे जहां इंडिया का उपयोग किया गया है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंडअप इंडिया आदि। क्या भाजपा अपने सोशल मीडिया हैंडल के नाम एख्व्4क्ष्दड्डुत्ठ को भी बदलेगी? यदि अन्य राजनैतिक पार्टियों के नाम को खंगाला जाए तो ऐसी कई पार्टियां मिलेंगी जिनके नाम में भारत, भारतीय, इंडिया, इंडियन शब्द अवश्य मिलेगा। तो फिर इस बेतुके विवाद को क्यों खड़ा किया जा रहा है? असल में भाजपा और एनडीए को जिस बात से अधिक परेशानी है, वो विपक्षी दलों का ऐसा ऐलान है, जिसका सामना भाजपा को आने वाले लोक सभा चुनावों में करना पड़ेगा। गौरतलब है कि विपक्षी नेताओं ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो लोक सभा चुनावों में भाजपा और एनडीए के हर प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया संगठन के तहत अपने सभी दलों का समर्थित एक प्रत्याशी ही उतारेंगे जो उस संसदीय क्षेत्र में काफी लोकप्रिय होगा।

विश्व मंच पर सोशल मीडिया के सहारे हिन्दी

उमेश चतुर्वेदी

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के तत्काल बाद उसकी महासभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। दूसरे विश्वयुद्ध और उससे हुए विनाश की काली छाया के बीच हुई उस बैठक में कई प्रस्ताव पारित हुए थे। लेकिन 10 जनवरी, 1946 को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसे संयुक्त राष्ट्र की पूरी दुनिया के जन-जन तक पहुंच का संकल्प कहा जा सकता है। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि जब तक दुनिया के हर व्यक्ति तक संयुक्त राष्ट्र की जानकारी नहीं पहुंच जाती, इसके उद्देश्यों को सही मायने में हासिल नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र ने यह संकल्प पारित तो किया, पर इसके लिए उसे जैसा वैविध्यपूर्ण भाषायी मंच चाहिए था, वह तब बना नहीं पाया। उस दौर की शासित भाषाएं- अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और बाद में चीन की मंदारिन ही उसकी आधिकारिक भाषा बन पाई। इसके बाद पेट्रो डॉलर के दम पर अरबी भी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन गई।

बहरहाल, देर से ही सही, संयुक्त राष्ट्र को अपनी पहली बैठक का संकल्प याद आया और उसने भाषायी वैविध्य को स्वीकार करना शुरू किया। भले ही संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार हिन्दी में बोलते रहे हों, विदेश मंत्री के नाते सुषमा स्वराज भी अपनी बात हिन्दी में कहती रहीं, लेकिन हकीकत यह है कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी की स्वीकार्यता को लेकर अभी लंबी दूरी तय किया जाना बाकी है। विदेश मंत्री रहते सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र की सूचनाओं को हिन्दी में ही पहुंचाने की कोशिश शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग ने साल 2018 में एक परियोजना शुरू की। इसके तहत वैश्विक संचार विभाग ने सोशल मीडिया और दूसरे मंचों के जरिये हिन्दी में सामग्री पहुंचाना शुरू किया। इस परियोजना का उद्देश्य हिन्दी में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों और उससे जुड़ी सूचनाओं की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना और लाखों हिन्दी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाना था। इस परियोजना ने पांच साल की अपनी यात्रा पूरी कर ली है।

वर्ष 2018 से ही दुनिया के करोड़ों हिन्दी भाषी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हिन्दी में ट्विटर अकाउंट और न्यूज पोर्टल शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र अब हिन्दी में पॉडकास्ट भी करता है। भारत के प्रयासों का ही नतीजा है कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित तमाम समाचार सोशल मीडिया और मीडिया के कई मंचों पर हिन्दी में जारी हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के हिन्दी ट्विटर अकाउंट के जहां 50 हजार फॉलोअर हैं, वहीं इसके इंस्टाग्राम पेज के 29 हजार और फेसबुक पेज के 15 हजार फॉलोअर हैं। साल 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र का हिन्दी इंटरनेट मीडिया अकाउंट सालाना करीब एक हजार पोस्ट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हिन्दी समाचार वेबसाइट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह इंटरनेट सर्च इंजनों में शीर्ष दस स्थान में शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र ने भले ही जन-जन तक अपनी पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा हो। लेकिन किसी भाषा को अपनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा उसका अपना ही चार्टर है। भाषा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। साथ ही आधे से ज्यादा देशों को उस भाषा को अपनाने पर होने वाले खर्च को वहन करना होता है।

भारत की आज जो वैश्विक स्थिति है, उसमें उसे हिन्दी के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का बहुमत जुटाना मुश्किल नहीं है। लेकिन हिन्दी की राह में सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त राष्ट्र के कामकाज की नियमावली की धारा 51 है, जिसके तहत सदस्य देशों की बहुसंख्या को उसका खर्च उठाने के लिए सहमति देनी होगी। भारत के सामने चुनौती इसी धारा का संशोधन कराना है।

बहरहाल जब तक नियमों की वजह से हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल नहीं हो जाता, तब तक उसे संयुक्त राष्ट्र के सोशल मीडिया मंचों के ही जरिये आगे बढ़ाया जाना चाहिए। भारत सरकार की सोच भी कुछ यही है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग को दस लाख डॉलर का चेक सौंपा जाना भी उसी प्रक्रिया का अगला कदम है।

यादों में रह जाएंगी छावनियां

रणधीर तेजा चौधरी

आने वाले दिनों में देश की छावनियों का स्वरूप सिरे से बदल जाने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित योल छावनी से यह शुरुआत हो चुकी है। योल छावनी को अब सैन्य अड्डे और असैन्य इलाके में बांटा जाएगा।

असैन्य इलाके का स्थानीय नगर पालिका में विलय कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस बाबत जारी अधिसूचना के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने छावनी बोर्ड योल के सिविल एरिया को धर्मशाला विकास खंड की पंचायतों में विलीन करने का आदेश दिया है।

देश की सभी छावनियों का स्वरूप इसी प्रकार बदला जाना है। छावनी क्षेत्र के लिए बजट रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा विभाग से आता है। बजट का एक हिस्सा असैन्य इलाकों पर खर्च होने से सैन्य इलाके को लगता है कि उसे जरूरत के मुताबिक बजट नहीं मिल पाता। सैन्य और असैन्य इलाकों के बीच बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी खींचतान जैसी स्थिति रहती है। इसलिए नागरिक इलाकों को छावनी क्षेत्र से अलग करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। 2019 में हिमाचल प्रदेश के छावनी क्षेत्र के लोगों ने सेना के दबाव से मुक्त करने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन भी चलाया था। उनका कहना था कि अपने मकानों में मरम्मत तक के लिए सैन्य अधिकारियों से मंजूरी लेनी होती है। पानी की आपूर्ति में जब-तब बाधित कर दी जाती है। गौरतलब है कि छावनियां औपनिवेशिक संरचनाएं हैं। योल कस्बे की स्थापना 1849 में हुई थी और यंग ऑफिसर्स लिविंग का संक्षिप्तीकरण है योल। पहले विश्व युद्ध के बाद यहां युद्धबंदियों को रखा जाता था। अलबत्ता, योल छावनी की विधिवत स्थापना 1942 में हुई थी। अब छावनी क्षेत्रों को स्थायी रूप से सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में बांटे जाने के फैसले की शुरुआत योल छावनी से कर दी गई है।

किसी छावनी क्षेत्र से आप गुजर रहे हों तो यह नहीं बता सकते कि वह कौन से शहर की छावनी है। सभी में गजब की एकरूपता है। पूरे दिन पीटी, परेड, क्लब कल्चर, खिलाड़ियों के मैदानों में जुटान आदि हर कैंट में दिखलाई पड़ता है। देश के हर प्रांत-क्षेत्र के लोग छावनी में रहते हैं। तमाम छावनियों का भूगोल एक जैसा होता है। हरियाली से ढंका। सुरक्षा का आलम यह कि छोटे बच्चे भी आसपास के बाजार और स्कूलों के मैदान में दिन के किसी भी पहर चहलकदमी कर आते हैं। पेड़ों पर चढ़कर उछल-कूद मचाने, चोर-सिपाही खेल खेलने, रास्ते में कहीं भी मिल जाने वाले पेड़ या झाड़ से आम या बेर तोड़ लेने जैसे नजारे यहां आम होते हैं। गुलाब की सोंधी सी खुशबू चहुंओर बिखरी रहती है। लोगों में सामाजिकता भी गजब की होती है। एक दूसरे की चिंता करने वाली।

छावनियां अंग्रेजों की देन हैं। देश में 62 छावनियां हैं। आजादी के समय 56 छावनियां थीं, और 1947 के बाद छह और छावनियां अधिसूचित की गई। इस क्रम में 1962 में अजमेर अंतिम 62वीं छावनी बनी। पहली छावनी बंगाल के बैरेकपुर 1765 में हुगली नदी के किनारे बसाई गई। इसे फ्रेंच के खिलाफ सतर्क रहने के मद्देनजर बसाया गया था। दरअसल, फ्रेंच ने हुगली नदी के दूसरी तरफ चंद्रनागोर (अब चंदननगर) को जीत कर वहां अपने सैनिकों को जमावड़ा कर लिया था। उसके जवाब में अंग्रेजों ने हुगली नदी के दूसरी तरफ छावनी आबाद की। बाद के समय में उन्होंने आगरा, रानीखेत, कसौली में अपने कब्जे में आए क्षेत्रों में छावनियां बसानी शुरू कर दीं। ब्रिटिशकाल में छावनियों का अपना अलग रुतबा था। ब्रिटिशराज समाप्त होने के बाद भी छावनियां बनी रहीं। यहां सैनिकों के फैमिली क्वाटर लाइन और बैरकें होती हैं। व्यवस्थित और उम्दा बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ। वाडरे में बंटे छावनी क्षेत्र से निर्वाचित वार्ड सदस्य छावनी क्षेत्र संबंधी फैसले लेते हैं, लेकिन बोर्ड का प्रशासक सैनिक अधिकारी होता है।

हाल के समय में रास्तों और सड़कों पर चलने के अधिकार को लेकर मसला उभरा। आतंकवाद के बाद से सैन्य क्षेत्रों की कुछ सड़कों पर आम आवाजाही प्रतिबंधित करने से नागरिक आबादी को परेशानी हुई। हालांकि 2018 में सरकार ने छावनी क्षेत्रों की सड़कों को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया था। सैन्य क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिक अफसर चाहते हैं कि सड़कों को आम लोगों के लिए न खोला जाए क्योंकि इससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। पिछले वर्ष सकिंदराबाद छावनी में सेना ने एक सड़क पर आम आवाजाही रोकी गई थी। सड़क का इस्तेमाल करने वाले साढ़े तीन लाख से ज्यादा सिविलियंस को वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ा और सड़कों पर भीड़भाड़ और अफरातफरी फैल गई। लोगों ने इस रोक के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस मांग के साथ कि ब्लॉक की गई सड़क को जनता के लिए खोला जाए।

जरा हटके जरा बचके की सफलता के बाद सारा ने खरीदा नया ऑफिस स्पेस

भगवान शिव की भक्त सारा ने हाल ही में अमरनाथ का दौरा किया और पवित्र गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद सारा ने इंस्टाग्राम पर यात्रा का वीडियो भी शेयर किया। सारा फिलहाल विक्की कौशल के साथ आई मूवी जरा हटके जरा बचके की सफलता का आनंद ले रही हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और दर्शकों के बीच इसकी सराहना की गई।

अब सारा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई हैं। सारा अनुराग बसु की मेट्रो...इन डिनो नाम की फिल्म में नजर आएंगी। इसके अलावा वे होमी अदजानिया की फिल्म मर्डर मुबारक में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक्ट्रेस सारा अली खान ने कुछ ही समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपना खास स्थान बना लिया है। उनकी एक्टिंग जितनी अच्छी है उतनी ही वे अपने व्यवहार के कारण भी फैंस के दिलों मे बस गई हैं। सारा कई प्रोड्यूसर-डायरेक्टर की पहली पसंद हैं। सारा ने हाल ही मे मुंबई में लोटस डेवलपर्स ग्रुप के लोटस सिग्नेचर बिल्डिंग में नया ऑफिस स्पेस खरीदा है। निर्माता आनंद पंडित लोटस ग्रुप के मालिक हैं। रियल एस्टेट वेबसाइट

की कीमत 1.01 करोड़ रुपए से लेकर 1.46 करोड़ के बीच हो सकती है। इसमें रजिस्ट्री चार्ज शामिल नहीं है। यह बिल्डिंग

बिल्डिंग दिसंबर 2025 तक लोगों को हैंडओवर कर दी जाएगी। फैंस में सारा को लेकर जबरदस्त क्रेज है और जब उन्हें एक्ट्रेस के इस कदम का पता चला तो वे सोशल मीडिया पर कमेंट करने के लिए उमड़ पड़े। आईए देखते हैं यूजर्स ने क्या-क्या लिखा बढ़ती रहो सारा। तुम्हें और अधिक सफलता मिले सारा। बहुत बधाई हो आपको सारा! आप इसी तरह खूब तरक्की करती रहें। हालांकि कुछ यूजर्स ने सारा पर तंज भी कसा। एक यूजर ने लिखा कि इंटरनेशनल रोमिंग पैक का रिचार्ज रोककर बचाए पैसों से आप इस

स्ट्रीट शॉपिंग कर आपने इतने पैसे बचा लिए कि यहां अपार्टमेंट लेकर इनवेस्ट किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सारा को मुंबई के बांद्रा मे स्ट्रीट शॉपिंग करते हुए स्पॉट किया गया था। सारा आम लोगों की तरह बाजार से सामान खरीद रही थीं।

अनुभव सिन्हा की फिल्म में साथ आएंगे राजकुमार और वाणी

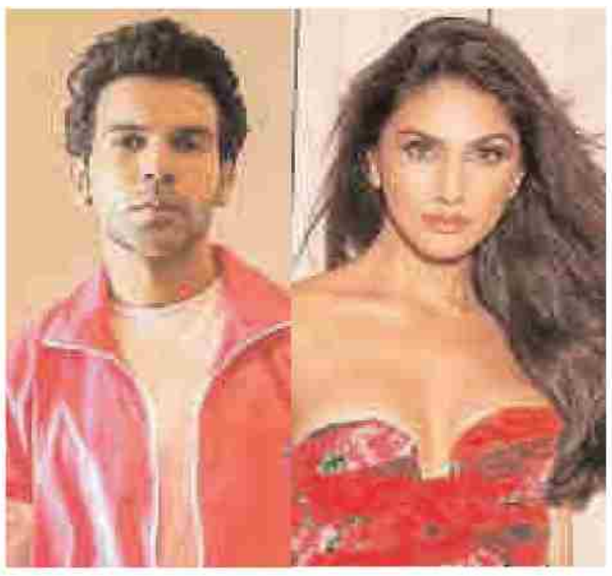

निर्माता अनुभव सिन्हा ने कई हिट फिल्में दी हैं। जिनमें आर्टिकल 15, मुल्क, थप्पड़ और भेड़ जैसी अपनी हिट फिल्में शामिल हैं। अनुभव सिन्हा अब अपने बैनर, बनारस मीडिया वर्क्स के तहत प्रोजेक्ट्स की एक नई सीरीज तैयार करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अनुभव सिन्हा चार प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हालांकि, अभी इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इनमें से एक में राजकुमार राव और वाणी कपूर हैं। अनुभव सिन्हा बचपन का प्यार नाम से एक छोटे शहर की प्रेम कहानी का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें राजकुमार राव और वाणी कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। यह लखनऊ में स्थापित एक अनोखी प्रेम कहानी है और इसका निर्देशन अपूर्व धर बडगइयां करेंगे, जिन्होंने पहले जितेंद्र कुमार-स्टारर रोमांटिक कॉमेडी चमन बहार का निर्देशन किया था। राजकुमार और वाणी दोनों ने फिल्म साइन कर ली है और अगले महीने किसी समय इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। जहां इस फिल्म के जरिए वाणी कपूर पहली बार अनुभव सिन्हा के साथ पहली बार काम करेंगे। वहीं राजकुमार राव का यह तीसरी बार होगा कि वह अनुभव सिन्हा के साथ काम कर रहे हैं। राजकुमार-वाणी की फिल्म के अलावा अनुभव सिन्हा एक और प्रेम कहानी का निर्माण कर रहे हैं, जिसका निर्देशन सुधीर मिश्रा करेंगे। दोनों फिल्म निर्माता श्रीलाल शुक्ला के राजनीतिक व्यंग्य उपन्यास, राग दरबारी और कोरोना वायरस महामारी पर एक संकलन की वेब सीरीज रूपांतरण पर भी एक साथ काम कर रहे हैं। बी पॉजिटिव नाम की इस संकलन का निर्देशन अनुभव सिन्हा, सुधीर मिश्रा, हंसल मेहता और केतन मेहता ने किया है और इस साल के अंत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसका प्रीमियर होने की उम्मीद है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा, सिन्हा द्वारा अक्टूबर 2023 में अपनी अगली निर्देशित फिल्म शुरू करने की भी उम्मीद है। वहीं, नेटफ्लिक्स इंडिया की बड़े पैमाने की हाईजैक ड्रामा सीरीज, आईसी 814 का फिल्मांकन कर रहे हैं, जिसमें विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर सहित अन्य कलाकार हैं।

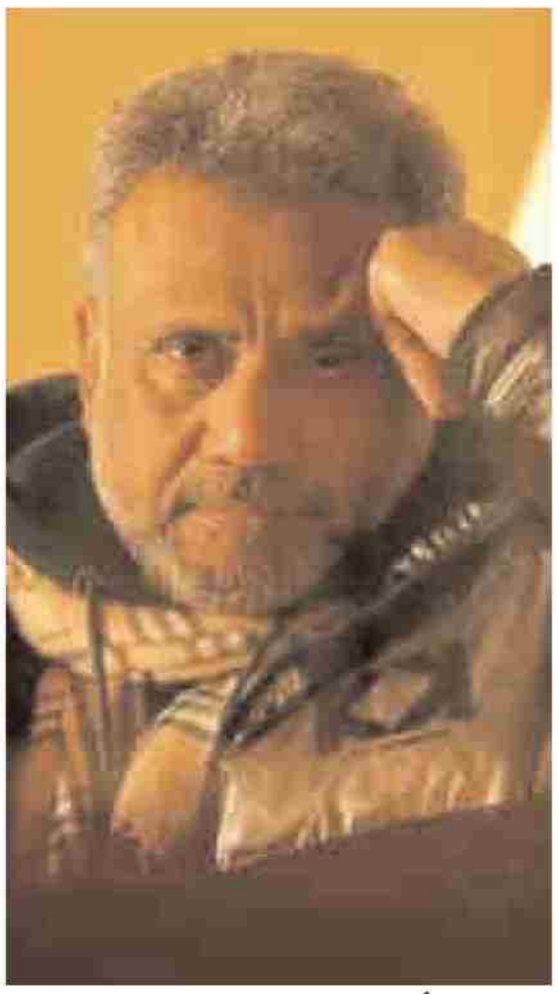

बचपन का प्यार लेकर आ रहे हैं अनुभव सिन्हा

निर्माता अनुभव सिन्हा ने कई हिट फिल्में दी हैं। जिनमें आर्टिकल 15, मुल्क, थप्पड़ और भेड़ जैसी अपनी हिट फिल्में शामिल हैं। अनुभव सिन्हा अब अपने बैनर, बनारस मीडिया वर्क्स के तहत प्रोजेक्ट्स की एक नई सीरीज तैयार करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अनुभव सिन्हा चार प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हालांकि, अभी इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पिंकविला ने खुलासा किया है कि इनमें से एक में राजकुमार राव और वाणी कपूर हैं। अनुभव सिन्हा बचपन का प्यार नाम से एक छोटे शहर की प्रेम कहानी का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें राजकुमार राव और वाणी कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। यह लखनऊ में स्थापित एक अनोखी प्रेम कहानी है और इसका निर्देशन अपूर्व धर बडगइयां करेंगे, जिन्होंने पहले जितेंद्र कुमार-स्टारर रोमांटिक कॉमेडी चमन बहार का निर्देशन किया था। राजकुमार और वाणी दोनों ने फिल्म साइन कर ली है और अगले महीने किसी समय इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। जहां इस फिल्म के जरिए वाणी कपूर पहली बार अनुभव सिन्हा के साथ पहली बार काम करेंगे। वहीं राजकुमार राव का यह तीसरी बार होगा कि वह अनुभव सिन्हा के साथ काम कर रहे हैं। राजकुमार-वाणी की फिल्म के अलावा अनुभव सिन्हा एक और प्रेम कहानी का निर्माण कर रहे हैं, जिसका निर्देशन सुधीर मिश्रा करेंगे।

भाबीजी घर पर हैं फेम सौम्या टंडन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

राज्यपाल ने चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश से किया सम्मानित

टीवी सीरियल भाबीजी घर पर हैं से घर घर अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने हाल ही में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। यह खुशी का पल एक्ट्रेस ने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सौम्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ब्लू नेट शिफॉन साड़ी में राज्यपाल से पुरस्कार लेती नजर आ रहीं हैं। राज्यपाल अपने हाथों में एक्ट्रेस को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश से सम्मानित कर रहे हैं। बता दें, चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार उन हस्तियों को दिया जाता है जो अपने काम और उपलब्धियों से समाज पर सकारात्मक असर डालते हैं। इस पुरस्कार के लिए बाकायदा एक ज्यूरी नाम तय करती है। सौम्या टंडन का परिवार भोपाल का रहने वाला है, ऐसे में उनको इस साल इस अवार्ड के लिए चुना गया है।

मुंबई से गोवा जा रहीं उर्फी जावेद के साथ फ्लाइट में हुई छेड़छाड़

टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उर्फी को चर्चा का विष्य बना देता है। उर्फी बेहद बॉल्ड और बेबाक एक्ट्रेस हैं। अपनी बात को लोगों के सामने खुलकर कहने की हिम्मत रखती हैं। लेकिन अब एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिस कारण उर्फी एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। दरअसल उर्फी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए बताया कि एक्ट्रेस फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में सफर कर रही थीं और तभी नशे में धुत कुछ लड़कों ने एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। उर्फी का कहना है कि वो पब्लिक फिगर हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। इस घटना के बाद एक्ट्रेस काफी गुस्से में हैं। उर्फी जावेद मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थीं। एक्ट्रेस छुट्टियां बिताने गोवा जा रहीं थीं, इस दौरान फ्लाइट में उर्फी के साथ कुछ लड़कों ने उनपर कमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक्ट्रेस ने उन लड़कों का वीडियो इंस्टाग्राम स्टेरीज पर शेयर किया।

टीवी के बाद रतन राजपूत ने साउथ इंडस्ट्री का किया पर्दाफाश

छोटे पर्दे के चर्चित शो अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वालीं रतन राजपूत फिलहाल पर्दे से दूर हैं। वहीं एक्ट्रेस अब सोशल मीडिया पोस्ट्स और व्लॉग के जरिए फैंस के साथ जुड़ती नजर आती हैं। बीते दिनों रतन ने टीवी इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच का कच्चा-चिट्ठा खोलकर हर किसी को हैरान कर दिया था। वहीं, अब उन्होंने साउथ इंडस्ट्री का काला सच उजागर किया है। साथ ही अपने ताजा बयान को लेकर हेडलाइंस का हिस्सा बन गई हैं। रतन राजपूत ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है कि लोग साउथ इंडस्ट्री को काफी आदर्शवादी समझते हैं, लेकिन वहां भी कास्टिंग काउच काफी ज्यादा प्रचलित है। रतन ने दावा किया है कि जब वह लाली की भूमिका में नजर आ रही थीं, तब उन्हें काम के लिए साउथ इंडस्ट्री से कई कॉल आए थे। हालांकि, उन कॉल पर एक्ट्रेस से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया था। रतन ने उन दिनों को याद करते हुए साउथ इंडस्ट्री के काले सच का पर्दाफाश करते हुए कहा, मुझे साउथ से कई फोन आते थे, कुछ बहुत अच्छे निर्देशकों से, लेकिन इसके साथ ही वे कहते थे कि रतन जी आपको थोड़ा वजन बढ़ाना होगा, आप बहुत पतली हैं। एक्ट्रेस ने साफ किया कि वह इस मांग पर सहमत हो गई थीं, लेकिन फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया। रतन ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप यहां के नियमों को पहले से ही जानती हैं। मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जानती हैं कि इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर (केवल लीड) और डीओपी भी हो सकते हैं। मैंने उनसे सीधे पूछा कि इसके बारे में क्या है, और फिर उन्होंने कहा कि आप जानती हैं, यहां आपको समझौता करना होगा। रतन राजपूत ने दावा किया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि आज तक उन्हें साउथ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, जहां उन्हें समझौता करने के लिए नहीं कहा गया हो। रतन ने कहा, लोग बॉलीवुड के बारे में जो बात कर रहे हैं, वही साउथ में भी होता है। टॉलीवुड अभी भी अच्छा काम कर रहा है, इसका कारण यह है कि वे अभी भी अपनी संस्कृति, रीति-रिवाजों, कपड़ों और हर चीज का सम्मान करते हैं।

रॉनी स्क्रूवाला का बॉलीवुड पर कटाक्ष

दर्शकों को हल्के में लेने पर भड़के प्रोड्यूसर

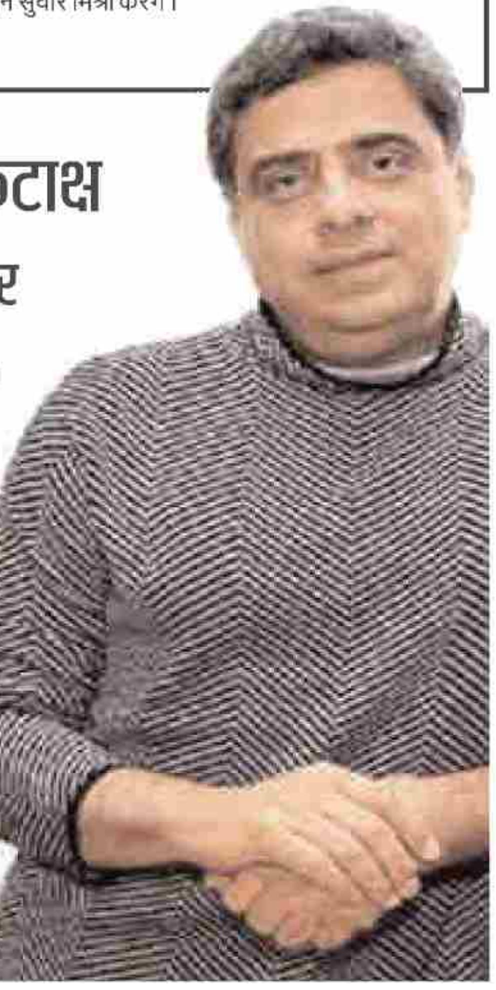

बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉक्स ऑफिस पर कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। जब से दुनिया में कोरोना महामारी आई, एक्टर्स और मेकर्स के लिए बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ना मुश्किल हो गया। वर्ष 2021-22 के बाद, द कश्मीर फाइल्स, सूर्यवंशी, ब्रह्मास्त्र और पठान जैसी फिल्में अपना जादू चलाने में सफल रहीं, लेकिन राम सेतु, लाल सिंह चड्ढा, विक्रम वेधा और रक्षाबंधन जैसी कई बिग बजट फिल्मों ने टिकट काउंटर पर दम तोड़ दिया, और फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो गई। इसी पर अब मशहूर प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कटाक्ष किया है। रॉनी स्क्रूवाला ने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडस्ट्री अब अपना सार खो रही है, और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रॉनी स्क्रूवाला ने दर्शकों को हल्के में लेने के लिए अन्य बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को आड़े हाथों लिया। इंटरव्यू में रॉनी स्क्रूवाला से पूछा गया कि बॉलीवुड ने अपना आकर्षण क्यों खो दिया है, तो उन्होंने कहा, मैं निर्णायक नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि हमने यहां अपने दर्शकों को हल्के में लिया है, और यही समस्या है। रॉनी स्क्रूवाला ने अपनी बात में आगे जोड़ा, जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं, जो आपके लिए वाक्य पूरा करते हैं, तो यह सबसे खतरनाक जगह होती है। हर बैठक में, कोई आपके लिए वाक्य पूरा कर रहा होता है, और आप बाहर जाकर कहते हैं क्या संस्कृति है। रॉनी यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा, क्षमा करें, लेकिन विविधता कहां है? बाहर क्या हो रहा है? आप इस भाग को कैसे समझेंगे? आपको कौन चुनौती देगा? आप अपनी ही दुनिया में हैं, आप ला ला लैंड में हैं। आपको ला ला लैंड से बाहर निकलने की जरूरत है।

बांग्लादेश में डेंगू का कहर...2,292 रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया गया

ढाका। बांग्लादेश में डेंगू महामारी का रूप ले चुका है। बांग्लादेश में 24 घंटों में कुल 2,292 डेंगू रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया यह 2023 में एक दिन में अस्पताल में भर्ती होने की सबसे अधिक संख्या थी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, इस अवधि के दौरान डेंगू से नौ और मौतें हुईं, जिससे संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 176 हो गई। नए मरीजों में से 1,064 को ढाका के अस्पतालों में और बाकी को बाहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पूरे बांग्लादेश में, राजधानी में 4,149 सहित 7,175 डेंगू मरीज अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस वर्ष अब तक डीजीएचएस ने डेंगू के 32,977 मामले और 25,626 ठीक होने के मामले दर्ज किए हैं। देश में साल 2022 में डेंगू से 281 मौतें हुई, जो 2019 में दर्ज की गई 179 मौतों के बाद रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। इसके अलावा, पिछले साल 62,423 डेंगू के मामले और 61,971 रिकवरी दर्ज की गई। अखबार ने बताया कि जुलाई सबसे खराब महीना रहा है, क्योंकि पिछले 21 दिनों में 109 मौतें और 20,465 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। डेंगू रोग-2023 के माह-वार आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में छह मौतों के साथ 566 डेंगू मरीज मिले। फरवरी में शून्य मौतों के साथ 111 मामले, मार्च में दो मौतों के साथ 143 मामले, अप्रैल में दो मौतों के साथ 50 मामले, मई में दो मौतों के साथ 1036 मामले और जून में 34 मौतों के साथ 5,956 मामले सामने आए। डीजीएचएस डेटा के अनुसार, तुलनात्मक रूप से पिछले साल डेंगू पॉजिटिव मामलों और मौत के आंकड़ों के मामले में कम गंभीर था। इस दौरान 268 मरीजों की मौत हुई थी और 62,382 मामले दर्ज किए गए थे।

चीन में स्कूल में बने जिम की छत गिरी, 10 लोगों की मौत

बीजिंग। चीन के पूर्वोत्तर शहर क्यूकीहार में एक मीडिल स्कूल में बने जिम की अचानक छत गिरने से 10 लोगों की मौत होने की सूचना है। जिम की छत के गिरने से मलबे में दबे 14 लोगों को निकाला भी गया है। बताया जाता है कि अभी एक शख्स मलबे में दबा हुआ है। उस निकालने का काम किया जा रहा है। हादसे के वक्त जिम में कुल 19 लोग मौजूद थे, जिसमें 4 लोग भागने में सफल रहे। यह घटना हेइलोंगजियांग प्रांत के क्यूकीहार में रविवार दोपहर करीब 3 बजे की घटित हुई। स्कूल नंबर 34 में यह जिम बना हुआ था जोकि अचानक ढह गया। मलबे में एक दर्जन से अधिक लोग फंस गए थे। इसके बाद राहत व बचाव अभियान चलाया गया जिसके बाद सोमवार सुबह तक 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है जिसमें 4 लोगों को मृत हालत में निकाला गया था। वहीं, 6 गंभीर रूप से घायल थे। इन घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छत पर मजदूरों ने पर्लाइट (ज्वालामुखीय कांच का एक रूप) रखा था। भारी बारिश के कारण पर्लाइट ने अधिक पानी सोख लिया। इससे पेर्लाइट आकार में फैल गया और अधिक भारी हो गया। इसके चलते छत ढह गई जबकि पर्लाइट से छत बनाना चीन में अवैध है। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में आगे की जांच की जा रही है और बचाव प्रयास अभी भी जारी हैं। बताया जाता है कि रेस?व?यू ऑपरेशन में करीब 160 अग्निशमन कर्मियों की टीम तैनात है।

कनाडा में भारतीय छात्र की हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

टोरंटो। कनाडा में फूड डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करने वाले एक 24 साल के भारतीय छात्र पर कार चोरों ने जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक गुरविंदर नाथ 9 जुलाई को रात करीब 2 बजे पिज्जा डिलीवरी कर रहे थे, तभी अज्ञात संदिग्धों ने उन पर हमला कर उनकी कार को लूटने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि 'मामले की जांच कर रहे अफसरों का मानना है कि इसमें कई संदिग्ध शामिल हैं और खाने का ऑर्डर ड्राइवर को इस इलाके में आने के लिए लुभाने के साधन के रूप में दिया गया था। पुलि ने हमले से पहले दिए गए पिज्जा ऑर्डर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल की है। पुलिस ने बताया कि गुरविंदर के पहुंचने के बाद उन पर 'हिंसक हमला कर एक संदिग्ध ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। संदिग्धों ने गुरविंदर की कार को लूट लिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग गए। नाथ को ट्रॉमा सेंटर ले जाने से पहले कई लोग उनकी मदद के लिए आए और सहायता की गुहार लगाई। जिसके बाद नाथ को अस्पताल ले जाया गया, जहां 14 जुलाई को नाथ को मृत घोषित कर दिया गया। टोरंटो में भारत के महावाणिज्यदूत सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि गुरविंदर नाथ की मौत एक 'दिल को दहलाने वाला नुकसान' है। उन्होंने कहा कि महावाणिज्य दूतावास ने नाथ की मौत के बाद उनके परिवार से संपर्क किया है। पुलिस ने बताया कि नाथ की कार हमले के कुछ घंटों बाद लावारिस हालत में पाई गई थी। जो अपराध की जगह से पांच किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। पुलिस ने कार की फोरेंसिक जांच की है और 'कई' सबूत बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नाथ और हमलावरों के बीच किसी रंजिश की जानकारी नहीं है। गुरविंदर नाथ का पार्थिव शरीर टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास की मदद से 27 जुलाई को भारत लाया जाएगा। नाथ जुलाई 2021 में भारत से कनाडा पहुंचे थे और उनकी अपना खुद का व्यवसाय खोलने की योजना थी। शनिवार को मिसिसॉगा में नाथ के लिए कैंडल लाइट मार्च में 200 से अधिक लोग एकत्र हुए। इस मौके पर लोगों ने कहा कि नाथ अपने परिवार की उम्मीदें लेकर कनाडा आए थे और अब उनका परिवार अपने तीन बेटों में से एक को खोने के गम से जूझ रहा है। नाथ के एक रिश्तेदार के दोस्त बॉबी सिद्धू ने कहा कि 'आप एक सपने के साथ कनाडा आते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक सपना चुरा लिया।

रोबोट ने कोल्ड वेल्डिंग तकनीकी से खुद अपना उपचार किया

न्यू मैक्सिको। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित सेंडिया नेशनल लैब के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में धातु के टुकड़ों को 200 वार प्रति सेकंड पर खींचा गया। इससे रोबोट में जो दरारें स्पष्ट रूप से झलकने लगी। प्रयोग के 40 मिनट बाद वह दरारें अपने आप भरने लगी। शोधकर्ताओं ने इसे कोल्ड वेल्डिंग का नाम दिया है। नेचर पत्रिका में शोध प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार कोल्ड वेल्डिंग मैटलर्जी की प्रक्रिया है। जिसमें धातु की दो मुलायम और साफ सतह अपने आप पास आती हैं। अपने एटामिक बांड को फिर से आपस में जोड़ लेते हैं। इस शोध से धातु यदि किसी तरह से अलग हो जाती है। तो इस पद्धति से उन्हें आपस में जोड़ा भी जा सकता है।

युद्धविराम समझौते के तहत अमेरिकी सैनिक के मामले में उत्तर कोरिया से की बात

वाशिंगटन। अमेरिकी सैनिक को हिरासत में लेने के मामले में उत्तर कोरिया से बातचीत शुरु की है। यह बातचीत युद्धविराम समझौते के तहत स्थापित संचार माध्यम से प्रक्रिया शुरू की गई है। जनरल एंड्रयू हैरिसन ने कहा कि इस युद्धविराम समझौते के तहत 1950-53 के कोरियाई युद्ध के तहत लड़ाई रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि पीवीटी ट्राविस किंग की सलामती कमान की मुख्य चिंता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र कमान के उप कमांडर ने कहा कि कमान ने हिरासत में लिए गए अमेरिकी सैनिक के मामले में उत्तर कोरिया के साथ बातचीत शुरू की है। सैनिक पिछले हफ्ते कोरियाई प्रायद्वीप की भारी सुरक्षा वाली सीमा को पार कर उत्तर कोरिया में प्रवेश कर गया था। जनरल एंड्रयू हैरिसन ने कहा कि युद्धविराम समझौते के तहत स्थापित संचार माध्यम से प्रक्रिया शुरू की गई है। इस युद्धविराम समझौते के तहत 1950-53 के कोरियाई युद्ध के तहत लड़ाई रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि पीवीटी ट्राविस किंग की सलामती कमान की मुख्य चिंता है।

कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण सीएन रेल लाइन पर से बहता हुआ पानी।

इंडोनेशिया में फिर समुद्री हादसा, 15 लोगों के मारे जाने की सूचना

जकार्ता। इंडोनेशिया में फिर समुद्री हादसे की खबर सामने आ रही है। सुलावेसी द्वीप पर एक नौका के डूबने से 15 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इतना ही नहीं 19 लोग अभी लापता भी हैं। रेस्क्यू टीम इन सभी की तलाश जोर शोर से कर रही है। हादसे के वव?त नौका में कुल 40 यात्री सवार थे। इसमें से 6 यात्री सही सलामत हैं। बीते अप्रैल माह में भी रियाउ प्रांत में नौका डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशियाई अधिकारी ने बताया कि सोमवार को सुलावेसी द्वीप पर एक नौका डूबने से कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। इसके बाद से 19 यात्री लापता भी हो गए हैं। जिनकी तलाश अलग-अलग रेस्क्यू टीमों की ओर से की जा रही है। इस नौका में कुल 40 यात्रियों के सवार होने की सूचना मिली है। इसके बाद बाद 6 यात्री भी हैं, जिनको सकुशल बचा लिया गया है। हालांकि नौका के डूबने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हादसा बीती आधी रात को हुआ था। खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख मुहम्मद अराफा ने कहा कि सभी पीड़ितों की पहचान कर ली गई है और उनके शवों को परिवार को सौंप दिया गया है, जबकि हादसे में बचे सभी 6 यात्रियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि 17,000 से अधिक द्वीपों वाले इंडोनेशिया में नौकाएं परिवहन का एक प्रमुख और सामान्य साधन हैं और यहां इस तरह की दुर्घटनाएं आम हैं। इस तरह के हादसों के पीछे एक बड़ी वजह नौका परिवहन को लेकर बनाए गए सुरक्षा मानकों का लचर होना और लाइफ स्पोर्ट सिस्टम का कमजोर होना है। गौरतलब है कि अप्रैल माह में भी पश्चिमी इंडोनेशिया के रियाउ प्रांत में इंद्रगिरि हिलिर रीजेंसी के टेम्बिलाहन कस्बे में एक बंदरगाह से निकलने के करीब 3 घंटे बाद नौका डूब गई थी। नौका डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य अब भी लापता हैं।

एलोन मस्क हमेशा के लिए उड़ा देंगे ट्विटर की नीली चिड़िया

Blue Bird की जगह लेगा X अक्षर

सैन फ्रांसिस्को (एजेंसी)। एलन मस्क अक्सर ट्विटर पर आश्चर्यजनक घोषणाएँ करते रहे हैं और इस ससाहांत भी कुछ अलग नहीं था। अरबपति ने घोषणा की कि ट्विटर की चिड़िया को एक्स अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। मस्क ने रविवार सुबह एक ट्वीट में लिखा, ÷और जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे-धीरे सभी पक्षियों को अलविदा कह देंगे।÷ मस्क ने बताया कि डोमेन ङ्ग.ष्शद्व उपयोगकर्ता को ट्विटर पर रीडायरेक्ट करता है। उन्होंने नए लोगो का भी संकेत दिया जो संभवतः ब्लू बर्ड की जगह लेगा।

ट्विटर का बदला जाएगा लोगो

सोशल मीडिया मंच 'ट्विटर' अब अपने 'लोगो' के लिए प्रसिद्ध नीली चिड़िया की जगह अंग्रेजी के 'एक्स' अक्षर का इस्तेमाल करेगा। उद्योगपति एलन मस्क ने रविवार को यह जानकारी दी। मस्क ने पिछले साल 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदा था। उसके बाद उन्होंने साइट में कई बदलाव किए हैं। मस्क ने रविवार देर रात ट्वीट करके बताया कि वह लोगो में बदलाव सोमवार को

ही करना चाहते हैं।

नीली चिड़िया की ट्विटर से होगी विदाई, एक्स अक्षर को जोड़ा जाएगा

मस्क ने लिखा, ''और जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और सभी चिड़ियां को अलविदा कह देंगे।'' विपणन सलाहकार कंपनी 'मेटाफोर्स' के सह-संस्थापक एलन एडम्सन ने कहा कि 'एक्स' से जुड़े मस्क के पुराने इतिहास को देखते हुए यह बदलाव आश्चर्यजनक नहीं है।

मस्क की रॉकेट कंपनी से है एक्स का कनेक्शन

टेस्ला के अरबपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में ट्वीट किया था, ''ट्विटर को खरीदना सभी सेवाएं मुहैया कराने वाली 'एक्स' ऐप की दिशा में उठाया गया कदम है।'' मस्क की रॉकेट कंपनी 'स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प' को आमतौर पर 'स्पेसएक्स' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1999 में 'एक्स डॉट कॉम' नामक एक स्टार्टअप की स्थापना की थी, जो एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी है। इसे अब पेपाल के नाम से जाना जाता है।

एलन मस्क ने नए लोगो का संकेत दिया

एलन मस्क ने अपने प्रोफ़ाइल पर एक वीडियो पिन किया है जो संभवतः नया ट्विटर लोगो हो सकता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने उसी लोगो को टेक्स्ट के रूप में पोस्ट किया। एक अन्य ट्वीट में मस्क ने लिखा कि X.com अब उपयोगकर्ता को Twitter.com पर ले जाता है और अंतरिम X लोगो जल्द ही लाइव होगा।

मणिपुर के वीडियो कांड पर अमेरिका भी चिंतित, घटना को क्रूर और भयानक बताया

वॉशिंगटन (एजेंसी)। मणिपुर के वीडियो कांड पर अमेरिका भी चिंतित नजर आया है। उसने इस घटना को क्रूर और भयानक बताया है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका ने रविवार को कहा है कि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले वीडियो की रिपोर्ट पर खासा चिंतित है। यह वह मामला है जिसने देश को गुस्से में डाल दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से इस घटना को क्रूर और भयानक बताया गया है। विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। गौरतलब है कि मणिपुर में मई के महीने से ही हिंसा जारी है। जहां कुकी समुदाय को दिए जाने वाले आर्थिक लाभों में बदलावों की आशंका के बाद से ही मैतेई समुदाय के साथ हिंसा शुरू हो गई। जो वीडियो अब सामने आए हैं वो मई के बताए जा रहे हैं। जहां जातीय संघर्ष के दौरान 21 और 19 साल की पीड़ितों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। जबकि एक महिला के साथ गैंगरेप और फिर हत?या की खबरें हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। पिछले हफ्ते ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

हालांकि पुलिस ने मामले में कुछ गिरफ्तारियां की हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका, मणिपुर हिंसा का शांतिपूर्ण और समावेशी समाधान चाहता है। साथ ही उसने अधिकारियों से सभी समूहों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग करते हुए मानवीय जरूरतों का जवाब देने का अनुरोध किया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वीडियो सामने आने के बाद हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कड़ी कार्रवाई का वादा किया। केंद्र सरकार की तरफ से 32 लाख की आबादी वाले मणिपुर में तैनाती के लिए हजारों अर्धसैनिक और सेना की टुकड़ियां भेजी। इसके बाद मामला कुछ समस्या शांत हो सका था। लेकिन इसके तुरंत बाद छिटपुट हिंसा और हत्याएं फिर से शुरू हो गईं और तब से राज्य में तनाव बना हुआ है।

रुस का यूक्रेन पर आरोप, आवसीय क्षेत्र में कर रहा ड्रोन से हमला

मॉस्को (एजेंसी)। रूस ने यूक्रेन को सोमवार सुबह हुए ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें मॉस्को की दो इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दो ड्रोन क्रैश हुए जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। रुसी मीडिया ने बताया कि एक ड्रोन रक्षा मंत्रालय के करीब गिरा। यूक्रेनी अधिकारियों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि उन्होंने कभी भी रूस के अंदर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि ड्रोन हमलों ने स्थानीय समयानुसार लगभग 04-00 बजे गैर-आवासीय इमारतों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमारतों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं कुछ ड्रोन के टुकड़े रक्षा मंत्रालय की इमारतों से सिर्फ 2 किमी दूर पाए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, मॉस्को शहर पर दो ड्रोन का इस्तेमाल करके कीव शासन की ओर से आतंकवादी हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, शहर के कोम्सोमोल्स्की एवेन्यू के किनारे ड्रोन का मलबा भी पाया गया। मॉस्को के परिवहन विभाग ने लिखा कि रास्तों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और तस्वीरों में आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर काम करती दिख रही हैं। लिकचेव एवेन्यू पर भी यातायात रोक दिया गया, जहां एक ऊंची ऑफिस बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। मॉस्को ने यूक्रेन पर हाल के महीनों में उसके क्षेत्र पर कई ड्रोन हमलों का आरोप लगाया है। इस महीने की शुरुआत में, रूस ने कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन हमला किया जिससे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। इसके पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर ओडेसा के पास ड्रोन नौकाओं के निर्माण और तैयारी करने वाली सुविधाओं पर रात भर मिसाइल हमला किया। बयान में कहा गया, पिछली रात, रूसी सशस्त्र बलों ने लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ उन सुविधाओं पर एक समूह हमला किया, जहां बिना चालक वाली नावों का उपयोग करके रूस के खिलाफ हमले के तैयारी की जा रही थी।

चांद से आगे की सैर भी कराएगा चीन का चंद्रयान, होगा नासा से मुकाबला

बीजिंग (एजेंसी)। भारत द्वारा लांच किए गए चंद्रयान-3 मून मिशन के बाद अब चीन भी स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन चीन का मिशन चांद से आगे की सैर कराने वाला है। जानकार बताते हैं कि दुनिया में चल रही स्पेस रेस में चीन एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहता है। हाल ही में भारत ने अपना चंद्रयान-3 मून मिशन लॉन्च किया है। अब चीन 2027 के आसपास नए जमाने के चालक दल वाले अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और उससे भी आगे ले जाने में सक्षम होगा। जानकारी के अनुसार चीन के ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम के डेप्युटी चीफ डिजाइनर यांग लिवेई ने कहा कि भविष्य में, एक नई पीढ़ी के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल हमारे स्पेस स्टेशन के निर्माण और गहरे अंतरिक्ष की खोज में किया जाएगा। यांग ने कहा कि पहली उड़ानें 2027 और 2028 के बीच होने का अनुमान है। चीन ने 2020 में स्पेसक्राफ्ट के बॉयलरप्लेट वेरिएंट का टेस्ट किया था। वापस आए कैप्सूल को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। नया अंतरिक्ष यान चीन की 2030 तक चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की योजना का हिस्सा है। स्पेसक्राफ्ट आंशिक रूप से दोबारा इस्तेमाल करने योग्य होगा और इसे लॉन्च करने के लिए एक नया रॉकेट विकसित किया जा रहा है जिसे हाल ही में लॉन्ग मार्च 10 नाम दिया गया।

गौरतलब है कि स्पेसक्राफ्ट का डीप-स्पेस वेरिएंट

तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होगा। वहीं एक लो अर्थ ऑर्बिट वेरिएंट चार से सात अंतरिक्ष यात्रियों को चीन के टिएनगॉग स्पेस स्टेशन तक ले जा सकेगा। चीन वर्तमान में अधिकतम तीन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के लिए शेनझोउ स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। यांग 2003 में शेनझोउ-5 मिशन पर सवार होकर ऑर्बिट में जाने वाले देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। शेनझोउ-16 का दल इस समय तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर सवार है। तीनों अंतरिक्ष यात्री लगभग छह महीने के लिए 30 मई को स्टेशन पर पहुंचे थे। चीन ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की घोषणा ऐसे समय पर की है जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस मिशन के तहत 2025 में एक बार फिर चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की तैयारी में जुटी हुई है।

अंजू के प्यार की पाकिस्तान में पड़ताल शुरू, नसरुल्ला के घर मीडिया का जमावड़ा

पेशावर (एजेंसी)। भारत में सीमा हैदर को लेकर जहां तफ्तीश चल रही है, वहीं पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने अब भारत की अंजू प्रसाद की लवस्टोरी की पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल 35 साल की अंजू जो भारत के उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्हें पाकिस्तान के नसरुल्ला से प्यार हो गया था। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वां की छोटी सी जगह अपर दीर के नसरुल्ला के साथ उनकी लवस्टोरी फेसबुक पर शुरू हुई थी। लेकिन अब इस फेसबुकिया लवस्टोरी की पाकिस्तान में जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हर बिंदु से मामले की जांच कर जाएगी। सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला ठीक उसी समय सामने आया है जब भारत में सीमा हैदर से पूछताछ शुरू हुई है। अंजू की तरह सीमा भी अपने प्यार की खातिर भारत आई थी। हालांकि वह गैर-कानूनी तरीके से यहां पहुंची थी। रविवार को जैसे ही अंजू के बारे में खबरें आनी शुरू हुई नसरुल्ला के घर के बाहर स्थानीय मीडिया का हुजूम इकट्ठा हो गया। इस दौरान अंजू ने पत्रकारों से कहा कि वह नसरुल्लह से प्यार करती है और वह उसके बिना नहीं रह सकती।

मीडिया को अंजू ने बताया कि उनकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और फिर उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। इसके बाद उन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। अंजू ने ट्रैवल वीजा के लिए अप्लाई किया। वीजा मिलने के बाद वह यहां पहुंच गई। यहां एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक अंजू और नसरुल्ला की दोस्ती की जांच की जा रही है। अंजू पहले से ही शादीशुदा है। अपर दीर के जिला पुलिस अधिकारी मुश्ताक खान ने पत्रकारों को बताया कि महिला उनके साथ है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला के पास वैध वीजा है और वह एक महीने तक रह सकती है। महिला को दोषमुक्त होने के बाद मीडिया के सामने पेश किया जाएगा।

इस मामले में एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि भारतीय महिला मीडिया से बच रही थी। उन्होंने कहा कि जब नसरुल्ला के आने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई पत्रकार उसके घर पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि अंजू उनके घर पर मौजूद नहीं थी। वहीं नसरुल्लाह ने मीडिया को बताया कि अगले दो से तीन दिनों में वह और अंजू सगाई करने वाले हैं। फिर दस से बारह दिनों के बाद वह भारत वापस चली जाएगी और फिर शादी के लिए आएगी। यह मेरी और अंजू की निजी जिंदगी है। उनका कहना था कि वो दोनों मीडिया से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने देश वापस आकर अपना काम फिर से शुरू करना चाहती है।

विश्वकप के लिए शुरुआती 15 खिलाड़ियों में शामिल नहीं सूर्यकुमार, राहुल और अय्यर को जगह मिलना तय

-ईशान और संजू दूसरे विकेटकीपर की रेस में शामिल

मुम्बई (एजेंसी)। इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विश्वकप क्रिकेट के लिए आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को शुरुआती 15 खिलाड़ियों में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों ईशान किशन और संजू सैमसन को इसमें जगह मिली है। विश्वकप को देखते हुए भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 जुलाई से शुरु हो रही तीन मैचों की सीरीज अहम मानी जा रही है। इसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखने के लिए मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर भी वेस्टइंडीज पहुंच गये है। वह कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ से एशिया कप से लेकर विश्व कप तक के लिए खिलाड़ियों को लेकर बात करेंगे। वहीं बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि सूर्यकुमार को विश्वकप के लिए केवल सिर्फ बैकअप के तौर पर ही रखा जाएगा क्योंकि एकदिवसीय में उनका रिकार्ड अच्छा नहीं है। सूर्यकुमार के एकदिवसीय के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 23 मैच की 21 पारियों में 24 की औसत से 433 रन ही बनाये हैं। इसमें 2 अर्धशतक लगाये हैं। उपना सबसे अधिक स्कोर 64 रन है।

साथ ही कहा कि लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर टीम में जगह बनाने की दौड़ में सूर्यकुमार से कहीं आगे हैं। सूर्या को विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिलेगी। वह रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में रखे जा सकते हैं।

ऋषभ पंत के उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्य विकेटकीपर के तौर पर लोकेश राहुल को जगह मिलना तय है। ऐसे में दूसरे विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन या संजू सैमसन में से किसी एक ही अवसर मिलेगा। अब देखना है कि वेस्टइंडीज सीरीज में दोनों में से टीम प्रबंधन किसे अवसर देता है। जिसको भी अवसर मिलेगा विश्वकप में उसको खेलना तय रहेगा।

सैमसन ने अबतक 11 एकदिवसीय की 10 पारियों में 66 की औसत से 330 रन बनाए हैं जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।

इसके साथ ही नाबाद 86 रन उनका सबसे अधिक स्कोर है। दूसरी ओर ईशान ने एकदिवसी की 13 पारियों में 43 की औसत से 510 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।

भारतीय टेनिस खिलाड़ी करमन ने इवान्सविल में जीता ऐतिहासिक खिताब

इवान्सविल (एजेंसी)। भारतीय टेनिस खिलाड़ी करमन कौर थांडी ने यहां आयोजित आईटीएफ डब्ल्यू60 इवान्सविल के फाइनल में यूक्रेन की यूलिया स्तारोदुब्तसेवा को हराकर एकल खिताब जीत लिया है। राउंडग्लास अकादमी की करमन ने रविवार को हुए फाइनल में अपने यूक्रेनी प्रतिद्वंदी को 7-5, 4-6, 6-1 से मात दी। इस जीत के साथ करमन सानिया मिर्जा के बाद अमेरिका में प्रो खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गयीं। करमन ने फाइनल तक पहुंचने के लिये पहले राउंड में मेक्सिको की मारिया फर्नांडा नवारो और दूसरे राउंड में अमेरिका की मारिबेला ज़मारिप्पा को हराया था। क्वार्टरफाइनल में अमेरिका की वाइल्ड कार्ड प्रवेशी एली किक को सीधे सेटों में हराने के बाद उन्होंने सेमीफाइनल में अमेरिका की मेकार्टनी केसलर को मात दी थी।

करमन वर्तमान में डब्ल्यूटीए एकल रैंकिंग में 261वें स्थान पर हैं और देश की दूसरे नंबर की महिला खिलाड़ी हैं। वह हाल ही में कनाडा के सास्काटून चैलेंजर डब्ल्यू60 की युगल स्पर्धा और अमेरिका में आयोजित डब्ल्यू60 सुमेर पाल्मेटो प्रो ओपन की एकल स्पर्धा में उपविजेता रही थीं। करमन राउंडग्लास टेनिस अकादमी के तकनीकी निदेशक और कोच आदित्य सचदेवा एवं उनकी टीम के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं।

कोच सचदेवा ने कहा, 'दो बार उपविजेता रहने के बाद यह जीत करमन का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये एक अच्छे समय पर आई है क्योंकि वह अमेरिकी ओपन में जगह बनाने के लिये खुद को तैयार कर रही हैं। उनका हालिया फॉर्म उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रमाण है। हमें उम्मीद है कि वह आगे भी इस फॉर्म को बनाए रख सकेंगी।'

टीम ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज रन जोड़ने में रोहित - यशस्वी ने किया कमाल

दुबई (एजेंसी)। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टेस्ट मैच में रोहित ब्रिगेड ने अपनी दूसरी पारी में तेजी से रन बनाए है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में दो विकेट के नुकसान पर 181 रन बना कर पारी घोषित कर दी है। इस दौरान इशान किशन ने ऋषभ पंत के बल्ले से धमाकेदार अर्धशतक भी जड़ा। मैच को बारिश के कारण बीच में रोकना भी पड़ा था। अब मेजबान टीम को 365 रनों का लक्ष्य मिला है, जिसमें दो विकेट खोकर टीम 76 रन बना चुकी है।

इस मैच में भारत ने शानदार रिकॉर्ड भी बनाया है। मैच में भारतीय टीम ने 100 रन सिर्फ 74 गेंद पर ही बना लिए है। भारत ने इस दमदार गति से रन बनाकर शानदार रिकॉर्ड भी बनाया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के पास आ गया है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने (57 रन, 44 गेंद, 5 फोर, 3 सिक्स) और यशस्वी जायसवाल (38 रन, 30 गेंद, 4 फोर, 1 सिक्स) की पारी खेली। मैच के दर्शकों को टेस्ट मैच में टी20 का मजा मिला। इस मैच में रोहित शर्मा ने सिर्फ 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। भारत से पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका की टीम के पास था। श्रीलंका की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में 80 गेंदों में 100 रन बनाए थे। श्रीलंका ने ये उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हासिल की थी।

दूसरे सत्र का अधिकांश खेल बारिश की भेंट चढ़ा, भारत को 301 रन की बढ़त

पोर्ट ऑफ स्पेन। (एजेंसी)। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन रविवार को यहां बारिश के कारण दूसरे सत्र में सिर्फ तीन ओवर का खेल हो पाया लेकिन भारत चाय तक अपनी कुल बढ़त को 301 रन तक पहुंचाने में सफल रहा। दूसरी पारी में भारत ने तूफानी शुरुआत करते हुए लंच से पहले सिर्फ 12 ओवर में एक विकेट पर 98 रन बनाए। बारिश के कारण लंच का ब्रेक जल्दी लेना पड़ा। लंच के बाद तीन ओवर में भारत ने 20 रन जोड़कर स्कोर दो विकेट पर 118 रन तक पहुंचाया। मेहमान टीम ने इस दौरान सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (30 गेंद में 38 रन) का विकेट गंवाया। इसके बाद दोबारा बारिश होने लगी और खेल रोकना पड़ा।

बारिश के कारण खेल रोके जाने के समय शुभमन गिल 10 जबकि इशान किशन आठ रन बनाकर खेल रहे थे। पांचवें दिन भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है और ऐसे में भारत वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में आउट करने के लिए पर्याप्त समय चाहेगा जिससे की श्रृंखला में क्लीनस्वीप कर सके। जायसवाल दूसरे सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। उन्होंने दूसरे सत्र के पहले ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद को स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में विकेटकीपर जोशुआ डा सिल्वा को कैच थमाया। कप्तान रोहित शर्मा (44 गेंद में 57 रन) ने

भी दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए सिर्फ 35 गेंद में अपना सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक बनाया। रोहित ने शेनन गैब्रिएल की गेंद पर फाइन लेग पर अल्जारी जोसेफ को कैच थमाया।

उन्होंने जायसवाल के साथ पहले विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने 23.4 ओवर में 60 रन पर पांच विकेट चटकाते हुए वेस्टइंडीज के निचले क्रम को ध्वस्त किया। वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत पांच विकेट 229 रन से की और 26 रन जोड़कर बाकी पांच विकेट भी गंवा दिए जिससे पूरी टीम 255 रन पर सिमट गई और भारत ने 183 रन की बढ़त हासिल की। मोहम्मद शमी और चोटिल जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में कैरेबियाई सरजमीं पर भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई कर रहे सिराज ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को सुबह के सत्र में उनका सामना करने में काफी दिक्कतें आईं। भारत को दिन की पहली सफलता पदार्पण कर रहे मुकेश कुमार ने दिलाई।

पाक क्रिकेटरों ने पीसीबी के सामने वेतन बढ़ाने के साथ ही कई और मांगे रखीं

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीसी) से वेतन बढ़ाने के साथ ही केन्द्रीय अनुबंध को बेहतर बनाने की मांग की है। पीसीबी का केन्द्रीय अनुबंध 30 जून को ही समाप्त हो गया है और इस समय पाक टीम बिना किसी करार के श्रीलंका में सीरीज खेल रही है। पाक खिलाड़ियों ने मुख्य रुप से चार मांग रखी है जिनपर श्रीलंका दौरे के बाद फैसला होने की संभावना है। वहीं पीसीबी के अनुसार अब तक खिलाड़ियों ने अनुबंध विस्तार के किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। खिलाड़ी पीसीबी की नई प्रबंधन समिति के प्रमुख जका अशरफ से बात करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पूर्व प्रमुख नजम सेठी के कार्यकाल में वेतन में 45 फीसदी बढ़ोतरी की जो बात हुई थी उसे अमल में लाया जाये। और खिलाड़ी इसी मांग हैं! पीसीबी के केन्द्रीय अनुबंध में शामिल खिलाड़ी दूसरे क्रिकेट बोर्ड की तुलना में वेतन चाहते हैं। इसके अलावा वे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा और शिक्षा को लेकर भी पॉलिसी चाहते हैं। वहीं प्रायोजकों का मानना है कि आईसीसी के इवेंट से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी के साथ ही विदेश लीग में हिस्सा लेने के लिए एनओसी जारी करने में और पारदर्शिता की जरुरत है।

नोआ लाइल्स ने तोड़ा उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड, जानें विश्व चैंपियन के बारे में पांच दिलचस्प तथ्य

नोआ लाइल्स ने मात्र 20 सेकंड से भी कम समय में सर्वाधिक 200 मीटर दौड़ को पूरा किया है। ये रिकॉर्ड अब तक उसेन बोल्ट के नाम था। ये उपलब्धि नोआ लाइल्स ने कुछ समय पूर्व ही हासिल की है। इस रिकॉर्ड के साथ ही नोआ लाइल्स चर्चा में आ गए है। नोआ लाइल्स ने 23 जुलाई को लंदन एथलेटिक्स मीट में लेटसाइल टेबोगो को हराकर 19.47 सेकंड के समय के साथ दौड़ जीती। 200 मीटर में 20 सेकंड के अंदर यह उनकी 35वीं दौड़ थी। इस जीत के साथ वो 20 सेकेंड से कम समय में रेस जीतने के मामले में उसेन बोल्ट से आगे निकल गए है। 26 वर्षीय खिलाड़ी नोआ लाइल्स ने पहले ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दोहरा प्रयास करने की योजना घोषित कर दी है। इस बार नोआ का लक्ष्य है कि वो चैंपियनशिप में जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीते। अगर उन्हें गोल्ड मेडल जीतने में सफलता मिलती है तो वो उसेन बोल्ट और एलिसन फेलिक्स के साथ मिलकर 200 मीटर में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि उसेन बोल्ट ने चार बार जीत हासिल की, जबकि लाइल्स पहले ही 2019 और 2022 में जीत हासिल कर चुके हैं।

बारिश के कारण चौथा टेस्ट ड्रॉ, ऑस्ट्रेलिया के पास बरकरार रही एशेज ट्रॉफी

मैनचेस्टर (एजेंसी)। बारिश ओर खराब मौसम के कारण यहां एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच हार-जीत के परिणाम के बिना ही समाप्त हो गया। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखने में सफल रही है। इसका कारण है कि गत वर्ष उसने एशेज सीरीज जीती थी। इस सीरीज में अब एक मैच ही बचा है और इंग्लैंड टीम उसे जीतती भी है तो भी सीरीज ड्रॉ रहेगी। ऐसे में नियमों के अनुसार एशेज ट्रॉफी गत विजेता के पास ही रहती है। इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में जीत के लिए पांच विकेट की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया को मेजबान टीम को फिर से बल्लेबाजी के लिए मजबूर करने के लिए 61 रनों की जरूरत थी। बेन स्टोक्स की टीम के पास ये मैच जीतने का अवसर था पर बारिश के कारण पांचवें दिन कोई खेल नहीं हो पाने के कारण उन्हें जीत का मौका नहीं

मिला। यह पहली बार है कि स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड टीम ड्रॉ पर मजबूर हुई है। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास अंतिम मैच जीत के साथ ही 2001 के बाद पहली बार इंग्लैंड में सीरीज़ जीतने का अवसर है।

वहीं मेजबान इंग्लैंड अब 27 जून से ओवल में शुरू होने वाले पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट को जीतने और श्रृंखला को 2-2 से बराबरी पर लाने के इरादे पर उतरेगी।

मैनचेस्टर में बारिश ने शनिवार को चौथे दिन के खेल के दो सत्र बर्बाद कर दिए थे। वहीं अंतिम दिन मौसम खराब होने के अनुमान था जो सही साबित हुआ। आउटफील्ड पर बड़े-बड़े गड्ढे बनने लगे। बारिश के कारण पिच निरीक्षण स्थगित होने के कारण दोपहर का भोजन जल्दी लिया गया।

खेल शुरू होने की कुछ उम्मीद बनी और दोपहर एक बजे खेल शुरू होने की घोषणा की गई पर बारिश के कारण खेल फिर से बाधित हो गया। इसके बाद शाम को मैच ड्रॉ की घोषणा कर दी गयी।

नोवाक जोकोविच ने टोरंटो टूर्नामेंट से नाम वापस लिया, जानें क्या रही वजह

टोरंटो। विम्लबडन फाइनल में कार्लोस अल्काराज से हारने के बाद नोवाक जोकोविच ने अतिरिक्त आराम के लिए नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट से भी नाम वापस ले लिया है। टेनिस कनाडा ने रविवार को घोषणा की कि जोकोविच थकान के कारण इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे। 23 बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन 36 वर्ष के जोकोविच को अमरीकी ओपन की तैयारी इस हार्डकोर्ट टूर्नामेंट से शुरू करनी थी। उन्हें पिछले रविवार को विम्बलडन फाइनल में अल्काराज ने पांच सेटों में हराया। चार बार नेशनल बैंक खिताब जीत चुके जोकोविच ने कहा, 'कनाडा में मुझे हमेशा अच्छा लगता है लेकिन अपनी टीम से सलाह लेने के बाद मैने तय किया कि यही फैसला सही है।% जोकोविच की जगह अब अमरीका के क्रिस्टोफर यूबैंक्स को मिली है जो विम्बलडन में अप्रत्याशित प्रदर्शन करके क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे।

भारतीय महिला और पुरूष टीमों की नजरें स्पेन में अच्छे प्रदर्शन पर

लाहौर (एजेंसी)। नई दिल्ली -भारतीय महिला और पुरूष हॉकी टीमें स्पेन के टेरासा में मंगलवार से शुरू हो रहे स्पेनिश हॉकी महासंघ की सौवीं वर्षगांठ वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेंगी। टूर्नामेंट में भारतीय पुरूष टीम का सामना इंग्लैंड, नीदरलैंड और मेजबान स्पेन से होगा जबकि महिला टीम इंग्लैंड और स्पेन से खेलेगी।

पुरूष टीम के लिए यह टूर्नामेंट तीन से 12 अगस्त तक चेन्नई में होने वाली हीरो एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी का सुनहरा अवसर है। उसके बाद चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल होने हैं। भारतीय पुरूष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, 'स्पेन में टूर्नामेंट से हमें कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खुद को आंकने का मौका मिलेगा। इससे हमें पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है जिससे एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी और एशियाई खेलों की तैयारी पुख्ता होगी।'

दूसरी ओर महिला टीम की कप्तान सविता ने कहा, 'स्पेन दौरे से हमें एशियाई खेलों की तैयारी में मदद मिलेगी। वहां फोकस रणनीति पर अमल करने और टीम भावना के साथ अच्छे प्रदर्शन पर होगा।' उन्होंने कहा, 'हम अपनी शैली में खेलेंगे लेकिन पिछले दौरे की कमियों की भरपाई भी करेंगे।'

एआईएफएफ ने महिला फुटबॉल ओलंपिक क्वालीफायर के लिए संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की

नयी दिल्ली। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने इस साल होने वाले एएफसी महिला ओलंपिक क्वालीफायर के दूसरे दौर की टीम के चयन के लिए सोमवार को राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेने वाली 34 खिलाड़ियों की घोषणा की। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने किर्गिस्तान को 5-0 और 4-0 से हराकर ओलंपिक क्वालीफायर के दूसरे दौर में जगह बनाई। भारत ताशकंद में होने वाले एएफसी महिला ओलंपिक क्वालीफायर के ग्रुप सी में 26 अक्टूबर को जापान, 29 अक्टूबर को वियतनाम और एक अक्टूबर को मेजबान उज्बेकिस्तान से भिड़ेगा। शिविर भुवनेश्वर में 30 जुलाई से शुरू होगा। संभावित खिलाड़ी इस प्रकार हैं।

गोलकीपर- सौम्या नारायणसामी, मेइबाम लिनथोइनगांबी देवी, श्रेया हुड्डा। डिफेंडर- लोइटोंगबम आशालता देवी, नगंगबम स्वीटी देवी, संजू, रितु रानी, सोरोखैबम रंजना चानू, मिशेल मार्गरेट कास्टन्हा, डालिमा छिब्बर, मनीषा पन्ना, अस्तम ओरांव, जूली किशन, सिल्की देवी, जाबामनी टुडु। मिडफील्डर- प्रियंगका देवी, अंजू तमांग, इंदुमती कथिरेसन, संगीता बासफोर, काजोल ह्यूबर्ट डिसूजा, आसिम रोजा देवी, कार्तिका अंगमुथु। फारवर्ड- डेंगमेई ग्रेस, सौम्या गुगुलोथ, मनीषा कल्याण, अपूर्णा नारजार, नेहा, सुमति कुमारी, रेनु, करिश्मा पुरूषोत्तम शिरवोइकर, संध्या रंगनाथन, प्यारी शाशा, ज्योति, नगंगोम बाला देवी।

शफीक और अबरार के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने बनाया दबदबा

कोलंबो (एजेंसी)। अबरार अहमद (69 रन पर चार विकेट) और नसीम शाह (41 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद अब्दुल्ला शफीक की आक्रामक पारी के दम पर पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन सोमवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली। श्रीलंका की पहली पारी को 166 रन पर समेटने के बाद पाकिस्तान ने पहले दिन स्टंप्स तक दो विकेट पर 145 रन बना लिये। स्टंप्स के समय सलामी बल्लेबाज शफीक 74 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और कप्तान बाबर आजम आठ रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। दो मैचों की इस श्रृंखला में पाकिस्तान 1-0 से आगे है।

श्रीलंका की पारी को सस्ते में समेटने के बाद पाकिस्तान ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवर में छह से अधिक की रन गति से रन बनाये। टीम ने 50 गेंद में 50 और 101 गेंद में रनों का शतक पूरा किया। शफीक ने इस दौरान 49 गेंद में अपने टेस्ट करियर का पांचवां अर्धशतक पूरा किया जबकि शान मसूद ने 44 गेंद में अपना पचासा जड़ा। असिता फर्नांडो ने पारी के तीसरे ओवर में इमाम उल हक (छह) को आउट करने के बाद अपने दूसरे स्पैल मे मसूद को चलता किया। मसूद ने 47 गेंद की पारी में चार चौके और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाये। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए शफीक के साथ 108 रन की तेज तर्रार साझेदारी की। शफीक जब 42 रन पर थे तब प्रभात जयसूर्या ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच टपका कर जीवन दान दिया। उन्होंने अब तक 99 गेंद की नाबाद पारी में सात चौके और दो छक्के लगाये हैं।

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का श्रीलंका का फैसला गलत साबित हो गया। बारिश के कारण मैच एक घंटा विलंब से शुरू हुआ लेकिन शुरू होते ही सलामी बल्लेबाज निशान मदुशंका (4) तीसरे ओवर में रन आउट हो गए। कप्तान दिमुथ करूणारत्ने ने शाहीन अफरीदी की गेंद कवर में खेली और रन लेने के लिये दौड़े लेकिन शान मसूद के थ्रो ने गिल्लियां बिखेर दी जबकि मदुशंका क्रीज तक नहीं पहुंचे थे। कुसल मेंडिस छह रन बनाकर अफरीदी की गेंद पर कवर में कैच दे बैठे। नसीम शाह ने एंजेलो मैथ्यूज (नौ) और करूणारत्ने (17) को लगातार दो ओवरों में आउट किया। श्रीलंका ने 36 रन पर चार विकेट गंवा दिये थे। धनंजय डिसिल्वा और दिनेश चांदीमल ने पांचवें विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी करके श्रीलंका को मैच में

वापसी कराने की कोशिश की। नसीम ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान चांदीमल को 34 रन पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। डिसिल्वा 57 रन बनाकर अबरार का शिकार बने। इन दोनों की साझेदारी टूटने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाज फिर से मैच पर हावी हो गये। रमेश मेंडिस (27) ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ टीम के स्कोर को 160 के पार पहुंचाया।

लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े नेताओं ने थाम बीजेपी का दामन

लखनऊ, 24 जुलाई (एजेन्सी)। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। सपा, रालोद और कांग्रेस के कई नेताओं ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में विपक्ष के साहब सिंह, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, पूर्व विधायक गुलाब सरोज और जगदीश सोनकर जैसे बड़े चेहरे पार्टी में शामिल हुए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा ने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक विपक्षी दलों को झटका देने की तैयारी की है। पश्चिमी यूपी में सैनी समाज का बड़ा वोट बैंक है। इस समाज के वोट पर साहब सिंह सैनी और राजपाल सिंह सैनी का खासा प्रभाव है।

राजपाल ने 2022 में खतौली से रालोद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। पूर्वांचल में जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर सीट से सपा विधायक रहीं सुषमा पटेल कुर्मी समाज से हैं, पार्टी पूर्वांचल में कुर्मी समाज में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है।

पूर्व विधायक जगदीश सोनकर चार बार विधायक रहे हैं। पूर्वांचल के सोनकर समाज में उनकी मजबूत पकड़ है।

2019 में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया। शालिनी कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यसभा में पूर्व उपसभापति रहे श्याम लाल यादव की पुत्रवधू हैं। शालिनी यादव ने 2019 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। जिस दिन उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी दिन उन्हें सपा ने पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया था। हालांकि, उससे पहले वह कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी में मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज भाजपा परिवार में सपा, आरएलडी और बसपा छोड़कर बहुत बड़ा समूह आ गया है। मैं राजपाल सैनी का स्वागत करता हूं। साहब सिंह सैनी, जगदीश सोनकर, अंशुल वर्मा, सुषमा पटेल, गुलाब सरोज, शालिनी यादव, राजीव बक्शी, आगरा से रवि भारद्वाज, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता यादव, पीयूष यादव, पुष्पेंद्र पासी, मुजफ्फरनगर से श्रीनिवास सैनी समेत सभी नए सदस्यों का अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि हम 2024 में यूपी की 80 सीट जीत रहे हैं। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। जीत का असर ऐसा होगा कि विपक्षी नेता सोंचेगे कि हम अपनी जमानत कैसे बचाएं।

प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर कई बड़े नेताओं ने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। मैं उनका स्वागत करता हूं।

सुत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत 5 हफ्ते के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं।

राजू ने कहा कि जांच एजेंसी चाहती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या किसी अन्य अस्पताल द्वारा जैन के स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारीख पर सुनवाई हो।

पीठ ने मामले की सुनवाई पांच सप्ताह बाद तय की।

शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।

ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज की गई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के बाद उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जैन को छह सितंबर 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी।

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ से याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई पर एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगन की मांग की थी। इसके मद्देनजर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया।

शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह मामला 9 अगस्त को सूचीबद्ध होने की संभावना है।

उमर खालिद की याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने रविवार को जवाबी हलफनामा दायर किया था, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मामले को 24 जुलाई के लिए पोस्ट कर दिया था। दिल्ली पुलिस के वकील ने हजारों पन्नों की चार्जशीट का हवाला देते हुए जवाब दाखिल करने का और समय मांगा था।

उमर खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि वह आदमी दो साल और ग्यारह महीने से हिरासत में है। कौन सा शपथ पत्र दायर करने के लिए है? यह एक जमानत याचिका है।

उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को नियमित जमानत की मांग करने वाली उमर खालिद की अपील खारिज कर दी थी।

उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार किया था।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान अमरावती में दिए गए कथित विवादित भाषण, दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद के खिलाफ आरोपों का आधार थे।

दिल्ली पुलिस के अनुसार दंगों से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में जेएनयू स्कॉलर और कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम शामिल हैं।

बता दें फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ने हिंसक रूप ले लिया था। जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

सभापति धनखड़ से टीएमसी सांसद की जुबानी जंग, संजय सिंह पूरे सत्र के लिए निलंबित

नई दिल्ली, 24 जुलाई (एजेन्सी)। राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ दिखा। एक तरफ राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं, सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया।

दरअसल, राज्यसभा में विपक्ष और सरकार के बीच पेच इस बात पर फंसा है कि मणिपुर पर चर्चा किस नियम के तहत हो। क्योंकि सरकार नियम 176 के तहत बहस करना चाहती है तो विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी नियमों को लेकर राज्यसभा में नोटिस जमा कराए गए थे।

सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान पहले नियम 176 के तहत मिले नोटिसों का विवरण देते हुए सांसदों और उनसे जुड़े राजनीतिक दलों के नाम पढ़े, जिनमें से ज्यादातर राजकोषीय पीठों से थे, जिसमें राजस्थान से लेकर मणिपुर तक के राज्यों में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी।

उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए 11 नोटिस मिले हैं। नोटिस देने वाले सभी सदस्यों के नाम के साथ उनके दल और उनके मुद्दों का उल्लेख किया और कहा कि सभी नोटिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

धनखड़ ने बताया कि भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर, भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठी चार्ज पर, भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर, भाजपा के जी वी एल नरसिम्हा राव ने छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण को लेकर अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं के प्रदर्शन पर, भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति से जुड़ी चिंता पर और भाजपा के ही घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर नोटिस दिए हैं। सभापति ने इसी प्रकार भाजपा के अन्य सदस्यों के नोटिस का उल्लेख किया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के डॉ. वी शिवदासन ने मणिपुर में जातीय हिंसा पर नोटिस दिया है। धनखड़ ने कहा कि आखिरी नोटिस को छोड़कर शेष सभी नोटिस पर वह गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जहां तक आखिरी नोटिस का सवाल है तो आपको याद होगा कि 20 जुलाई को मैंने इस बारे में अपनी व्यवस्था दे दी थी। मणिपुर में हिंसा को लेकर दिए गए नोटिस मैंने स्वीकार कर लिए थे। उन्होंने कहा कि उसी दिन सदन के नेता पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से कहा था कि उन्हें इन नोटिस पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

वहीं, जब उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से नियम 267 के तहत प्राप्त नोटिस को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने पार्टी के नाम का उल्लेख नहीं किया। बता दें, विपक्षी दल मणिपुर मुद्दे पर लंबी चर्चा की मांग कर रहे हैं। सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने के लिए 27 नोटिस मिले हैं।

उन्होंने जैसे ही उल्लेख करना आरंभ किया कि तो टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने आपत्ति जताई और सभापति से पूछा कि ये सदस्य किस दल के हैं, उनका भी जिक्र किया जाना चाहिए। धनखड़ ने डेरेक से उनकी सीट पर बैठ जाने को कहा, लेकिन तृणमूल नेता ने अपनी बात जारी रखी। तृणमूल नेता ने कहा कि आपने जैसे भाजपा के सदस्यों का नाम लिया, वैसे ही अन्य नोटिस देने वालों के दल का भी उल्लेख कीजिए। इस पर सभापति ने कहा कि डेरेक ओब्रायन, आप कुर्सी को चुनौती दे रहे हैं।

वहीं, राज्यसभा ने सोमवार को मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान आप सांसद संजय सिंह को उनके अनियंत्रित व्यवहार के लिए मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव पेश होने से पहले, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सिंह को उनके अनियंत्रित व्यवहार के लिए चेतावनी दी थी। बता दें, संजय सिंह मणिपुर मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रहे थे।

सिद्दारमैया समर्थकों ने की हरिप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग

बेंगलुरु, 24 जुलाई (एजेन्सी)। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी कलह दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थक परिषद में विपक्ष के नेता बी.के. हरिप्रसाद द्वारा सीएम की पोस्ट पर उनकी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

इस घटनाक्रम ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हरिप्रसाद ने कहा था कि वह भीख नहीं मांगेंगे और जानते हैं कि सीएम को कैसे गिराना और बनाना है।

इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। सिद्धारमैया के समर्थक मांग कर रहे हैं कि हरिप्रसाद को परिषद में विपक्ष के नेता के पद से बर्खास्त किया जाए।

इस बीच, गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा है कि पत्रकारों को हरिप्रसाद से ही पूछना चाहिए।

कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि यह सब मीडिया की उपज है। हरिप्रसाद ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है।

अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं का इस मुद्दे पर कोई रुख न अपनाना और सीएम सिद्धारमैया का समर्थन न करना, यह कहता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।

डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार सीएम पद न मिलने से भी नाखुश हैं। उनके खेमे का कहना है कि वह 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे।

सिद्धारमैया के कट्टर समर्थक आवास मंत्री बी.जेड. ज़मीर अहमद खान और एन. चेलुवरयास्वामी ने सीएम के लिए वकालत की है और हरिप्रसाद की आलोचना की है।

इस बीच सिद्धारमैया खेमा पार्टी से हरिप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें नोटिस भेजने का आग्रह कर रहा है।

केपीसीसी सचिव वरुणा महेश ने एक वीडियो जारी कर आग्रह किया है कि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बोलने के लिए हरिप्रसाद को नोटिस दिया जाना चाहिए।

सूत्र बताते हैं कि हरिप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं है, क्योंकि उनके आलाकमान से करीबी संबंध हैं और गांधी परिवार से भी उनके अच्छे संबंध हैं।

हरिप्रसाद भी प्रभावशाली एडिगा समुदाय से हैं, जो ओबीसी श्रेणी में आता है।

आरएसएस, हिन्दुत्व और बीजेपी के खिलाफ उनके तेजतर्रार भाषण मशहूर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने हरिप्रसाद को नोटिस जारी करने के संबंध में अब तक कोई बयान नहीं दिया है।

हरिप्रसाद ने कहा था, 'मुझे कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, यह अलग बात है। कांग्रेस के पांच मुख्यमंत्रियों के चयन में मेरी भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। मैंने पिछड़े वर्ग के नेता को सीएम बनाया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सीएम कैसे बनाना है और साथ ही मैं उन्हें गद्दी से उतार भी देता हूं।'

उन्होंने कहा था कि वह पदों के लिए भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने परोक्ष रूप से सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा था, 'मैं लड़ाई लड़ूंगा। अन्यथा, मैं बेंगलुरु में 49 साल तक राजनीति नहीं कर पाता। मुझे भगा दिया गया होता। हमारे अपने लोग उनके साथ आते हैं, हमें शोषण नहीं करना चाहिए।'

एडिगा, बिलावा, दिवारा समुदाय के नेता सामने नहीं आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद वे राजनीति में आगे नहीं आ पा रहे हैं। 'इसे देखकर इस बात पर संदेह पैदा होता है कि क्या समुदाय के नेता साजिश का शिकार हो रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया पिछड़े वर्ग से हैं। हमने एकजुट होने के इरादे से 2013 में उनका समर्थन किया था। समर्थन देने के बाद, हम पदों के लिए याचना नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा, 'हमने उडुपी जिले के करकला शहर में कोटि चन्नय्या पार्क के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा था, सीएम सिद्धारमैया ने धन मुहैया कराने का वादा किया था। लेकिन, आज तक यह मंजूर नहीं किया गया है। वह राजनीतिक रूप से मेरी मदद करने की स्थिति में नहीं हैं। वास्तव में मैं उनका समर्थन करूंगा। पिछड़ा वर्ग एक जाति तक सीमित नहीं है। हम विभिन्न वर्गों और जातियों के अंतर्गत आते हैं। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए।'

हरिप्रसाद ने आगे कहा कि 11 विधानसभा सीटों पर एडिगा, बिलावा और दिवारा समुदाय निर्णायक स्थिति में हैं। 'मैं चुनाव समिति में भी था। इन समुदायों के चार उम्मीदवार टिकट पाने से चूक गए। मंगलुरु उत्तर और दक्षिण सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। अल्पसंख्यकों को टिकट आवंटित करने के बहाने, हमारे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट से वंचित कर दिया गया है,'

उन्होंने आरोप लगाया।

हरिप्रसाद ने कहा, 'भविष्य की पीढ़ी को लाभ होना चाहिए। वह (सिद्धारमैया) धार्मिक मठाधीशों से कह रहे हैं कि समुदाय से पहले से ही एक मंत्री है और दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। हमें संगठित होना होगा, अन्यथा हमारा शोषण किया जाएगा।'

इस घटनाक्रम ने कांग्रेस नेतृत्व को चिंतित कर दिया है क्योंकि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ विद्रोह के स्पष्ट संकेत हैं।

कांग्रेस पार्टी इस समय आंतरिक कलह झेलने की स्थिति में नहीं है, जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मंच तैयार है, जिसे कर्नाटक से मुख्य ताकत मिलेगी। देखना होगा कि आलाकमान इस स्थिति से कैसे निपटता है।

जरूरी समान लेकर गुवाहाटी से पहली मालगाड़ी मणिपुर पहुंची

इम्फाल/गुवाहाटी, 24 जुलाई (एजेन्सी)। जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री के संकट के बीच पहली मालगाड़ी सोमवार को गुवाहाटी से राज्य के तमेंगलोंग जिले के खोंगसांग रेलवे स्टेशन पहुंची।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद, जो 29 मई से 1 जून तक मणिपुर में थे, रेलवे प्राधिकरण ने असम के परिवहन विभाग के सहयोग से रविवार को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ियों को मणिपुर के लिए रवाना किया।

ट्रेन के खोंगसांग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद थे।

सिंह ने बाद में ट्वीट किया : 'आज खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन मालगाड़ी के महत्वपूर्ण आगमन को देखकर खुशी हुई।'

'यह विकास मणिपुर के लोगों के लिए ढेर सारे अवसरों की शुरुआत करता है, माल और आवश्यक वस्तुओं के त्वरित परिवहन का वादा करता है। निर्बाध रसद निस्संदेह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी, व्यापार को बढ़ाएगी और अंततः जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि करेगी।'

'इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से राज्य की आर्थिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं।'

महाराष्ट्र से ख़्याज, पश्चिम बंगाल से आलू और असम से एफएमसीजी उत्पाद पहले ही मणिपुर के लिए बुक किए जा चुके हैं।

एनएफआर के प्रमुख पीआरओ सब्यसाची डे ने कहा कि तामेंगलांग जिले में खोंगसांग रेलवे स्टेशन को आवश्यक वस्तुओं और अन्य खाद्य पदार्थों की

लोडिंग और अनलोडिंग के लिए खोल दिया गया है।

खोंगसांग नवीनतम स्टेशन है जिसे 2022 में जिरीबाम-इम्फाल नई लाइन परियोजना में चालू किया गया था।

एनएफआर 111 किमी लंबी जिरीबाम-इम्फाल रेलवे परियोजना का निर्माण कर रहा है, जिसने पहले ही 94 प्रतिशत की भौतिक प्रगति हासिल कर ली है और इस साल दिसंबर तक पूरा होने वाला है।

सीपीआरओ ने कहा कि मणिपुर में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण लाइन को पहले निलंबित कर दिया गया था, रेलवे के माध्यम से वस्तुओं को बुक करने के लिए मणिपुर स्थित व्यापारियों की सुविधा के लिए इम्फाल में एक विपणन निरीक्षक को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है।

व्यापारियों के किसी भी प्रश्न के लिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे।

अधिकारी ने कहा, मणिपुर के सभी व्यापारी अब खोंगसांग स्टेशन से आवश्यक वस्तुओं की बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

डे ने कहा कि राज्य के लिए विशेष विचार के तहत फिलहाल वैगनों की टुकड़ों में बुकिंग की अनुमति दी गई है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com